● वर्ष-4
● अंक-50
रायपुर, शनिवार
05 अक्टूबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

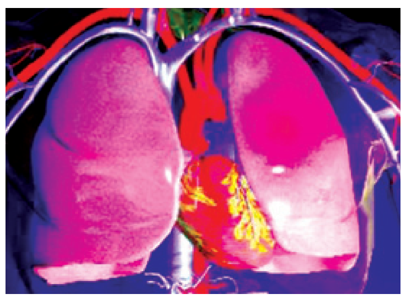

पेज-6»»» युवाओं के दिल पर अटैक!

सुरक्षाबलों ने मार गिराए 40 माओवादी

नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा हुई मुठभेड़, 24 नक्सलियों के शव बरामद, सभी जवान सुरक्षित

नारायणपुर/दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 40 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर सुरक्षाबल के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। मौके से बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ जारी है। 24 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी मुठभेड़ जारी है। रात होने की वजह से पुलिस मुठभेड़ में कुल कितने नक्सली मारे गए हैं यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। 40 से ज्यादा भी मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्चिंग जारी है। सूत्रों की माने तो करीब 40 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जवान नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना वाली जगह पर पहुंचे तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद सुरक्षाबल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में 40 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। क्षेत्र में रुक- रुक कर गोलीबारी हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में सभी जवानों के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है।

कल सुबह तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी- आईजी- बस्तर संभाग के आईजी पी. सुंदरराज के मुताबिक 24 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। पूरा अपडेट आने में समय लगेगा क्योंकि रात का समय है। रुक-रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। एक-47, एसएलआर समेत कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं।

नक्सलवाद का खात्मा ही लक्ष्य

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव राय ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षाबल के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जवानों को मिली यह बड़ी कामयाबी सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी, इसके लिए हमारी डबल इंजन सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। सीएम साय ने कहा कि सुशासन की सरकार में बस्तर अब शांति और विकास की ओर अग्रसर है। बीजापुर प्रवास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के साथ यहाम के विश्रामगृह में आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सली हिंसा से पीड़ित युवा, जो पुलिस विभाग में भर्ती होकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे संवाद किया और सभी ने अपना अनुभव साझा किया।

इतने माओवादी हुए ढेर

- **27 मार्च-** बीजापुर जिले के चिपुरभट्टी-पुसबाका के पास वन क्षेत्र में एक नक्सली डिप्टी कमांडर समेत छह नक्सलियों को मार गिराया था।
- **2 अप्रैल** - बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली और लेंड्रा के जंगल में तीन महिला नक्सली समेत 13 नक्सलियों को मार गिराया था।

6 अप्रैल - तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा पर पुजारी कांकेर के करींगुटा के जंगलों में मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर हुए थे।

- **16 अप्रैल-** कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गये थे। पुलिस फोर्स और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव ढेर हो गया था।
- **30 अप्रैल** -अबूझमाड़ के टेकामेटा के जंगलों में मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुरुष नक्सली शामिल थे।
- **10 मई** - बीजापुर जिले के पीड़िया के जंगल में 12 नक्सली मारे गए। इस दौरान दो जवान घायल भी हुए थे।
- **23 -24 मई** - नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ के बाद मौके से आठ नक्सलियों के शव मिले।
- **25 मई-** सुकमा और बीजापुर जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर हुए थे। 8 जून अबूझमाड़ के आमदई एरिया में छह नक्सली मारे गये।
- **15 जून** - नारायणपुर जिले के ओरछा थाना के फरसबेड़ा-धुरबेड़ा के बीच सुरक्षाबलों की नक्सलियों के मुठभेड़ में आठ नक्सलियों ढेर किए गए।

लाल आतंक पर शाह का प्लान

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास (23 से 25 अगस्त) के दौरान नक्सल प्रभावित सात राज्यों की अंतरराज्यीय समन्वय समिति की बैठक ली थी। इसमें नक्सल सातों राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अर्द्धसैनिक बलों के ऑफिसर शामिल हुए थे। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की गई थी। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सरेंडर करें या फोर्स की कार्रवाई के लिए तैयार रहे।

मार्च 2026 तक देश हो जाएगा नक्सल मुक्त- केंद्रीय गृहमंत्री ने 24 अगस्त की बैठक में कहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। हम मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह से नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूती के साथ रुथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा चैलेंज है।

नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील - अमित शाह ने अपील करते हुए कहा था कि जो वामपंथी उग्रवाद में लिप्त या जुड़े हो, सभी युवाओं से अपील है कि भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास, आपके विकास, आपके परिवार के विकास के लिए कटीबद्ध है। नक्सल की नई पॉलिसी को अच्छा प्रतिसाद दीजिए। हथियार छोड़िए और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो विकास का रथ चल रहा है। एक नए युग का जो आगाज हो रहा है, उसे मजबूती दें। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो रास्ता अख्तियार किया है, उसके मुताबिक पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कर देंगे।

ये सात राज्य बैठक में हुए थे शामिल - बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शिरकत कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिले- देश के 38 जिलों में से छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली नक्सल प्रभावित जिले हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अमित शाह ने सरकार बनने के बाद प्रदेश की जनता से नक्सलवाद को खत्म करने का वादा किया था।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल के 100 दिन

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के 100 दिन के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि वह जनता की सच्ची आवाज बन गए हैं तथा वंचितों एवं पीड़ितों के साथ खड़े हुए हैं। बता दें कि, राहुल गांधी इस साल लोकसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस पार्टी को इस साल हुए लोकसभा चुनावों में 99 सीटों पर जीत मिली थी। जिसके बाद उन्हें ये पद दिया गया था।

राहुल गांधी के 100 दिनों को लेकर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले 100 दिनों में राहुल गांधी बेजुबानों की आवाज बने हैं। उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए आवाज उठाने से लेकर अन्यायपूर्ण सरकारी नीतियों का विरोध करने जैसे मुद्दों को उठाया। वे वंचितों और उत्पीड़ितों के साथ खड़े नजर आए।

मणिपुर हिंसा के प्रभावितों की आवाज बने

पवन खेड़ा ने कहा कि, पिछले कई महीनों से चल रही मणिपुर हिंसा के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हिंसा से पीड़ित लोगों से बातचीत की और संसद में इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने सरकारी नौकरी में लेटरल एंट्री का विरोध किया। जिसके चलते सरकार को इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रियाओं का बचाव किया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि, राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का विरोध किया और प्रवेश परीक्षाओं में जवाबदेही की मांग करके सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को चुनौती दी। यही नहीं राहुल गांधी ने लोको पायलटों की दयनीय स्थितियों का मुद्दा उठाया, ट्रेन सुरक्षा की दिक्कतों को उजागर किया। जिसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था।

सेना में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की पैरवी की

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बजट में इंडेक्सेशन लाभ और पूंजीगत लाभ कर को प्रभावित करने वाले खंड का विरोध किया। जिससे कारण एक बार फिर सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ एक साहसिक कदम उठाया और सेना में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की पैरवी की।

कांग्रेस नेता ने कहा, राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को लेकर अपना पक्ष रखा, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन के कई दलों को भी इस मांग के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। वह स्वतंत्र मीडिया की आवाज को दबाने के उद्देश्य से बनाए गए प्रसारण विधेयक के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। राहुल के नेतृत्व की बदौलत, इस विधेयक को रद्द कर दिया गया।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज

पलवल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पांच अक्तूबर को होने वाले मतदान की तैयारियां चुनाव आयोग द्वारा पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 लागू की हुई है। मतदान केंद्रों पर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ और पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने निरीक्षण किया। वहीं पलवल के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को मतदान की आवश्यक सामग्री और ईवीएम देकर रवाना किया गया। उधर, होडल विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को राजकीय महाविद्यालय होडल से अंतिम रिहर्सल उपरांत चुनाव से संबंधित सामग्री व सामान उपलब्ध कराकर संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है।

नौ साल बाद दौरा, विदेश मंत्री जयशंकर 15-16 अक्तूबर को पाकिस्तान जाएंगे

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की तल्खी किसी से छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में केवल दो ही चर्चित अवसर रहे हैं जब देश का शीर्ष नेतृत्व पड़ोसी देश पाकिस्तान के दौरे पर गया हो। पहला अवसर खुद पीएम मोदी की यात्रा थी जब वे पहले कार्यकाल में अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पास पहुंचे थे। इसके बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान दौरा किया था। दिसंबर, 2009 में सुषमा के पाकिस्तान दौरा करने के बाद एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब भारत का केंद्रीय मंत्री या शीर्ष नेतृत्व पाकिस्तान के दौरे पर गया हो। अब आगामी 15-16 अक्तूबर को विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं। यह मौका लगभग नौ साल यानी 106 महीने बाद आ रहा है। दरअसल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को बताया कि इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे।

उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री जयशंकर के पाकिस्तान दौरे पर एक प्रतिनिमंडल साथ जाएगा। बता दें कि इस्लामाबाद में एससीओ समिट आगामी 15-16 अक्तूबर को प्रस्तावित है। शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के अलावा कजाखस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के शीर्ष नेता भी शरीक होंगे।

इससे पहले 3-4 जुलाई को अस्ताना में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे।

रोज हजारों लोगों को लूट रहे साइबर जालसाज

शशिधर पाठक

एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराधियों ने 2023 में दुनिया भर से छह खरब डालर लूट लिए थे। अनुमान है कि 2024 में यह आंकड़ा 8 खरब अमेरिकी डालर को पार कर जाएगा। इसमें एक बड़ा हिस्सा लूटे गए भारतीयों का भी होगा। साइबर सुरक्षा मामलों के उच्चतम न्यायालय के वकील पवन दुग्गल कहते हैं कि हमारे तो हाथ बंधे हैं। न देश के पास कोई प्रभावी कानून है और न ही साइबर अपराधों को रोकने और इससे निपटने की प्रभावी तकनीक। थेल्स कंपनी के साइबर सुरक्षा विंग को सेवाएं दे रहे पवन कुमार कहते हैं कि स्थिति बहुत विकट है।

थेल्स प्रोफेशनल का कहना है कि साइबर सुरक्षा की चिंता के घेरे में देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के गांव, कस्बे, शहर हैं। बताते हैं कोविड-19 के बाद यह खतरा कई गुना बढ़ गया है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की भी एंट्री हो गई है। लार्सन टुब्रो की सिस्टर आईटी कंपनी माइंड ट्री के सीनियर अधिकारी राजेश चौधरी कहते हैं कि अभी तो मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ने साइबर अपराध के साथ खेलना शुरू किया है। अभी तो इसका उछल-कूद मचाना बाकी है। राजेश चौधरी भी उन लोगों में से हैं जिनकी पत्नी को भी कभी साइबर ठगों ने ठग लिया था। वह कहते हैं कि देश का पढ़ा, लिखा, अंग्रेजी और हिंदी जानने वाला भी साइबर ठगों के जाल में बहुत तेजी से आ रहा है।

पवन दुग्गल कहते हैं कि देश की जनता साइबर लूट को सहने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि सरकार के पास राजनीतिक इच्छा

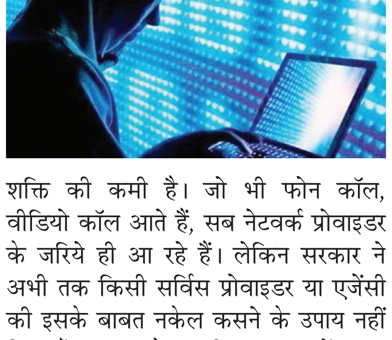

शक्ति की कमी है। जो भी फोन कॉल, वीडियो कॉल आते हैं, सब नेटवर्क प्रोवाइडर के जरिये ही आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक किसी सर्विस प्रोवाइडर या एजेंसी की इसके बाबत नकेल कसने के उपाय नहीं किए हैं। दुग्गल के मुताबिक 2013 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था, लेकिन तकनीक और अपराध के तिलिस्म में यह पूरी तरह से निष्प्रभावी है। दुग्गल कहते हैं कि अखबारों में तमाम साइबर अपराध की खबरें आ रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार कान में तेल डालकर बैठी है। इसके कारण साइबर अपराध पूरे देश में कॉटेज इंडस्ट्री बनता जा रहा है।

साइबर ठगी के हथकंडे....

पवन दुग्गल को फोन आया। फोन से पूरा आभास था कि यह ट्राई(टेलीफोन रेगुलेटरी अथारिटी आफ इंडिया) की तरफ से है। इसमें साफ कहा गया कि फोन के दुरुपयोग, पोर्नोग्राफी और लोगों को गाली देने का कारण दो घंटे बाद आपका फोन बंद हो जाएगा। इसके बाद निर्देश आने लगते हैं कि इस मामले को जानने के लिए एक दबाइए। एक्जीक्यूटिव से बात करने के लिए दो दबाइए और फिर पैसा उगाही शुरू हो जाती है।

संवाददाता के पास भी ऐसा ही एक फोन आया कि उसके पास तीस हजारी की अदालत गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। वारंट और विवरण जानने के लिए फलां बटन दबाइए। ओम प्रकाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनके पास फोन आया और व्हाट्सअप फोन नंबर देने का अनुरोध किया गया। इसके बाद ठगों ने ओम प्रकाश को एक युवती के साथ बात कराकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

सबसे दिलचस्प वाकया सुनील कुमार से हुआ। सुनील कुमार बंगलूरू से अपने घर आए थे। अचानक उनके फोन पर सूचना आई कि बंगलूरू एयरपोर्ट पर चेक इन के दौरान उनके सामान से एक पैकेट गिर गया था। इसमें सुरक्षा अधिकारी को ड्रग्स मिला था। सुनील कुमार थोड़े ही समय में साइबर ठगों के जाल में फंस गए। इसके बाद उन्हें ब्लैकमैल करके धन की उगाही शुरू हो गई।

रुपया लेते बाबू का वीडियो आया सामने

सीसी रोड की फाइल बढ़ाने मांग रहे थे रुपए, जनपद पंचायत जैजैपुर में पदस्थ है बाबू

■ इसी तरह तकनीकी सहायक की भी आडियो वायरल हुआ था जिसकी कार्यवाही आज तक अधर में

जैजैपुर। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने शासन लगातार प्रयासरत है उसके बावजूद भी कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे रिश्वत की मांग करने और लेने से बाज नहीं आ रहे। जनपद कार्यालय जैजैपुर में पदस्थ कर्मचारी द्वारा सड़क निर्माण कार्य का भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई और सीसी कैमरे में कैद होने के बाद कर्मचारी ने दलील दी कि यह उधार में दिए पैसों के ब्याज की राशि है।

यह पूरा मामला जनपद कार्यालय जैजैपुर का है। बताया जाता है कि जनपद पंचायत कार्यालय जैजैपुर में पदस्थ बाबू वेंकटेश्वर वर्मा ने ग्राम पंचायत बर्रा में विधायक निधि से निर्मित सीसी रोड का चेक दिये जाने के नाम पर सरपंच को महीनों से तरह तरह के बहाने बनाकर घुमा रहे है। जबकि सरपंच पंचायत में विधायक निधि से बनने वाले सीसी रोड का निर्माण पूर्ण करा करा कर बकाया भुगतान राशि लेने के लिए बाबू का चक्कर लगा रहे थे। सरपंच द्वारा बार बार बाबू से चेक काटने की निवेदन करने के बाद भी बाबू द्वारा चेक नही काटा जा रहा था। तब परेशान होकर सरपंच ने दूसरे व्यक्ति के माध्यम से बाबू को रुपये के साथ भेजा तभी उस व्यक्ति ने रुपये देते बाबू का वीडियो बना लिया। जनपद पंचायत जैजैपुर के सरपंचों ने बताया बाबू वेंकटेश्वर वर्मा लंबे समय से जैजैपुर जनपद कार्यालय में पदस्थ है और उनके द्वारा बिना रुपये लेनदेन के कोई भी कार्य नही करने का आरोप लगाया है।

लोगों को उधार में रकम देना और ब्याज लेना कानूनन अपराध है, अगर कोई ब्यक्ति ब्याज में रुपये देने का कार्य करता है तो उस व्यक्ति को शासन से लाइसेंस लेना रहता है। बाबू वेंकटेश्वर वर्मा के पास ना तो सूदखोरी का लाइसेंस है और ना उ किसी को ब्याज में रुपये दिया था। उसने तो ग्राम पंचायत बर्रा में सीसी रोड के निर्माण कार्य के चेक काटने और फाइल आगे बढ़ाने के लिए रुपये की मांग कर रहा था जो स्पष्ट रूप सुनाई दे रहा है।

आपको बता सरकारी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों का शासन के द्वारा समय समय पर ट्रांसफर किया जाता रहता है। ताकि कोई भी अधिकारी एक ही जगह पर ज्यादा दिन रहकर वहां कार्य ना करे। लेकिन जनपद पंचायत जैजैपुर में पदस्थ बाबू सालों से जैजैपुर जनपद पंचायत में बाबूगिरी कर रहे है। जिसके चलते यहां उसका जान पहचान स्थानीय लोगों सहित जनप्रतिनिधियों से हो गया है। यही कारण है बिना लेन देन के बाबू वेंकटेश्वर वर्मा द्वारा किसी भी पंचायत के कार्यों का फ़ाइल बढ़ाने के एवज में रुपये की मांग करना आम बात हो गई है।

पूर्व में भी एक तकनीकी सहायक की भी कमीशनखोरी का ऑडियो क्लिप 3 परसेंट लेने की बात करते हुए वायरल हुआ था जिसका भी आज पर्यंत तक कार्यवाही नही हुई है।

जनपद पंचायत जैजैपुर बाबू वेंकटेश्वर वर्मा ने कहा जिसे रुपये उधार दिये थे मैंने उसका ब्याज चुकाने वह व्यक्ति मेरे पास आया था और ये वही रुपये हैं।

भाजपा नेता हत्या के मामले में एनआईए ने छापामारी की

नारायणपुर। भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या के मामले में फिर एक बार नारायणपुर के कौशलनार इलाके में आज एनआईए ने छापामारी की है। विधानसभा चुनाव के दौरान रतन दुबे की भरे बाजार में हत्या कर दी गई थी, मामले में जल्द बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। विदित हो कि चार नवंबर 2023 को ग्राम कौशलनार साप्ताहिक बाजार में भाजपा नेता रतन दुबे को चुनाव प्रचार के दौरान उसकी सरेआम हत्या कर दी थी। नक्सल विरोधी अभियान के तहत 11 दिसंबर 2023 को नारायणपुर पुलिस ने चार संदेहियों को पकड़ा था, इनमें से एक बड़ेनहोड़ पारा कोंगेरा निवासी धनसिंग कोर्राम ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वह रतन दुबे की हत्या में शामिल था। घटना की जांच पहले स्थानीय पुलिस कर रही थी। इस साल फरवरी महीने में एनआईए ने रतन दुबे हत्या के मामले को अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की।

ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

कोयला लदे वाहनों पर रोक लगाने और सड़क मरम्मत की मांग

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा से नैला मुख्यमार्ग की सड़क पर बड़ी संख्या में जावलपुर के ग्रामीणों में चक्का जाम किया है। कोयला लोड ट्रेलर वाहन पर दिन में रोक लगाने और सड़को की जर्जर हालत को ठीक करने को लेकर यह चक्का जाम किया जा रहा है। भारी संख्या में बड़ी गढ़ियो की कतार लगी है आवागमन प्रभावित होने से राहगीरों को समस्या हो रही है। मौके पर पुलिस टीम और राजस्व अधिकारी पहुंचकर समझाने का प्रयास जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत बलौदा से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली एक मात्र मुख्य मार्ग है। जिसमे ग्राम पंचायत जावलपुर के ग्रामीण मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है जिससे कोयला लोड ट्रेलर वाहन की लंबी कतारें लगी है वही आम नागरिकों को भी आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने 30 सितंबर को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था जिसमे सड़क की मरम्मत और भारी वाहनों को दिन में नही चलाने पर रोक लगाने की मांग की थी और 3 दिनो का समय भी दिया गया था।

ग्रामीणों का कहना है की लगातार सड़क दुर्घटना से कोई न कोई परिवार अपना एक सदस्य खो रहा है। किसी ने पति खोया तो किसी ने बच्चे खोए आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। सड़को पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके है पैदल चल भी नहीं सकते है। स्कूल के समय भी तेज रफ्तार से वाहन को चलाया जाता है जिससे कई बार बच्चे मरते मरते बचे है।

आज शुक्रवार की दोपहर से 1 बजे से सड़क पर महिला, पुरुष, स्कूली बच्चे भी इस चक्का जाम में बैठकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे बाजी कर रहे है। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे हुए है 3 घंटो से लागतार चक्का जाम किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है की कई बार समस्याओं के संधान के लिए कलेक्टर आकाश छिकारा को जानकारी दी गई मगर कलेक्टर ने केवल बैठक में ही निपटारा किया धरातल पर कोई काम नहीं किया है जिससे आज हमे चक्काजाम करना पड़ रहा है।

भिलाई में शराब दुकान के खिलाफ सुपेलावासियों का प्रदर्शन

भिलाई। वैशाली नगर में एक बार फिर शराब दुकान को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है। यहां युवा शक्ति संगठन जिला प्रशासन से शराब दुकान बंद करने की मांग पिछले कई दिनों से कर रहा है। शुक्रवार को युवा शक्ति संगठन ने जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। हालांकि धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटा दिया। पुलिस का कहना है कि धरना प्रदर्शन के लिए संगठन ने पुलिस से परमिशन नहीं ली थी।

दरअसल भिलाई का सुपेला इलाका भीड़-भाड़ वाला इलाका है। यहां गांधी चौक पर एक अंग्रेजी शराब दुकान थी, जिसे वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने आबकारी अधिकारियों को बोलकर हटवा दिया था। सुपेला के ही लक्ष्मी नगर मार्केट में देसी शराब की दुकान है। उस देसी शराब दुकान के पास में ही एक और नई अंग्रेजी शराब दुकान खुल गई है। इसे लेकर अब एक बार फिर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब दुकान के कारण सुबह से लेकर रात तक क्षेत्र का माहौल खराब रहता है। लोग शराब पीकर गाली-गलौज करते हैं। यहां राह चल रही महिलाओं से अभद्र व्यवहार भी करते हैं, जिससे व्यापारियों की दुकानदारी पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के साथ-साथ विधायक से भी शराब की दुकानों को हटाने की अपील की है।

युवा शक्ति संगठन उपाध्यक्ष शारदा गुप्ता ने कहा हमारे तरफ से परमिशन के लिए एसडीएम के पास आवेदन दिया गया था, लेकिन दो दिन छुट्टी होने के कारण हमें परमिशन दिया गया। इस पर राजनीति की जा रही है। इसके चलते ही हमें पुलिस ने आंदोलन करने से रोका है।

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने कहा सुपेला स्थित शराब भट्टी हटाने को लेकर कुछ लोगों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उनके पास धरना प्रदर्शन का कोई परमिशन नहीं था। इसलिए हमें हटना पड़ा।

बता दें कि वैशाली नगर के गांधी चौक पर अक्सर शराब दुकानों को लेकर आंदोलन हुए हैं। शुक्रवार को हो रहे आंदोलन के दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों को परमिशन न होने की बात कहकर हटा दिया। युवा शक्ति संगठन ने मामले में राजनीति होने की बात कही है।

बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला

नाजायज संतान को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार

बिलासपुर। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता मृतक सरकारी कर्मचारी का नाजायज पुत्र हो, वह अनुकंपा के आधार पर विचार के लिए हकदार होगा। कोर्ट ने एसईसीएल प्रबंधन को नोटिस जारी कर कहा है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी करें।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार में अभाव और गरीबी को रोकना है। एक बार जब हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में विवाह के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे को वैध माना जाता है तो अनुच्छेद 14 के अनुरूप राज्य के लिए ऐसे बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने से वंचित करना उचित प्रतीत नहीं होता।

बता दें कि एसईसीएल में

आम गार्ड मुनिराम कुर्रे की मृत्यु 25 मार्च 2004 को हो गई थी। उसकी मृत्यु के समय ग्रेच्युटी नामांकन फॉर्म 'एफ' में सुशीला कुर्रे का नाम दर्ज था और पेंशन नामांकन फार्म में विमला कुर्रे का नाम था। विमला कुर्रे के साथ उनकी चार बेटियां मनीषा लाल, मंजूसा लाल, ममिता लाल, मिलिंद लाल और बेटा विक्रांत भी थे।

याचिकाकर्ता ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पेश किया था। मामले की सुनवाई कोरबा के प्रथम सिविल जज वर्ग एक के कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने भविष्य निधि 4,75,000/- और ग्रेच्युटी राशि 95,000 रुपए याचिकाकर्ता, उसकी मां और बहनों के पक्ष में प्रदान करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सुशीला कुर्रे ने अधिनियम, 1925 की धारा 383 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए आवेदन दायर कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया और सुशीला ने आवेदन वापस ले लिया।

समझौते के बाद कोर्ट ने 6 मार्च 2006 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता, उसकी मां विमला कुर्रे और बहनों को मुनिराम कुर्रे (मृतक) का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आदेश में कहा गया है कि विमला कुर्रे, मुनिराम कुर्रे की पत्नी है और सेवानिवृत्ति लाभों के उद्देश्य से याचिकाकर्ता मुनिराम कुर्रे का पुत्र है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों से यह तय हो गया है कि याचिकाकर्ता विक्रांत, मुनिराम कुर्रे का विमला कुर्रे के साथ विवाह से उत्पन्न पुत्र है।

अबूझमाड़ में सात नक्सलियों के मारे जाने की खबर

नारायणपुर/दंतेवाड़ा। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान अबूझमाड़ के जंगल में फोर्स की मुठभेड़ माओवादियों से हुई है। एनकाउंटर नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बार्डर एरिया पर हुई है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर दोपहर एक बजे शुरु हुई। पुलिस ने बताया है कि इलाके में रुक रुककर दोनों ओर से गोलाबारी हो रही है। पुलिस के आला अधिकारी ने बताया है कि मुठभेड़ में सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नक्सल ऑपरेशन से लौटने के बाद मुठभेड़ के बारे में पूरी जानकारी फोर्स की ओर से जारी की जाएगी। दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि अभी सात नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस के मुताबिक फोर्स रुटीन सर्चिंग अभियान पर निकली थी। जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को जंगल के भीतर नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली। फोर्स जैसे ही आगे बढ़ी नक्सलियों ने फायरिंग शुरु कर दी। जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। नारायणपुर और दंतेवाड़ा पुलिस पार्टी की संयुक्त टीम फिलहाल मुठभेड़ स्थल पर डटी है। दोनों ओर से रुक रुककर गोलीबारी की जा रही है। पुलिस के आला अफसर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।

पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा सात नक्सलियों के मारे जो की खबर मिल रही है। पुष्टि होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज मुखबिर से सूचना मिली की जंगल में नक्सली जमा हैं और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलने के बाद फोर्स को मौके के लिए रवाना किया गया। फोर्स को आता देख माओवादियों की ओर से गोलीबारी शुरु की गई। जवानों ने भी नक्सलियों को करारा जवाब दिया। जवानों को भारी पड़ता देख मौके से नक्सली पीछे हट गए। हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

महादेव सट्टा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। महादेव सट्टा एप घोटाला केस में जेल में बंद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। ये घोटाला देशभर में हज़ारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई नामचीन कारोबारी शामिल हैं। जमानत के लिए याचिकाएं लगाने वालों में नितिन तिबरेवाल, सूरज चोखानी, अमित अग्रवाल और गिरीश तलरेजा जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह माना कि इतने बड़े आर्थिक अपराध और जनता के साथ किए गए इस धोखे में जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि महादेव सट्टा एप घोटाला एक हाई-प्रोफाइल केस बन चुका है, जिसमें आरोप है कि इस एप के जरिए देशभर में अवैध सट्टेबाजी चलाई जा रही थी। आरोपी कारोबारी और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों से भारी रकम ठगते थे, जिसके चलते पूरे देश में कई जगहों पर छापेमारी और गिरफ्तारी की गई।

बाल संप्रेक्षण गृह से चार अपाचारी बालक फरार

महासमुन्द। महासमुंद में बाल संप्रेक्षण गृह बरोंडाबाजार से चार अपाचारी बालक फरार हो गए। अपचारी बालकों ने ड्यूटी पर तैनात नगर सैनिक और अटेंडेंट को पत्थर से मारकर घायल कर दिया और गेट की चाबी लेकर चारों फरार हो गए। दोनों घायलों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। चारों अपाचारी बालकों में 02 चोरी, 01 रेप और 01 गांजा तस्करी मामले में शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह लाये गये थे। इनमें 02 गरियाबंद, 01 बलौदाबाजार और 01 सरायपाली का निवासी है। बाल संप्रेक्षण अधिकारी ने कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी है। पुलिस चारों अपचारी बालकों की तलाश में जुटी है। इसके पहले भी कई बार अपाचारी बालक फरार हो चुके हैं। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद।

कार से गांजा तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

कोंडागांव। जिला कोण्डागांव के थाना अनंतपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले आरोपी कृष्णा साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उमरकोट से कोण्डागांव की ओर जा रही लाल रंग की स्वीफ्ट कार (वाहन क्रं. सी.जी. 04 पी.ए. 1630) में अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अखिलेश धीवर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अमरावती वैभव पेट्रोल पम्प के सामने मेन रोड एसएच-26 पर घेराबंदी कर वाहन को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी कृष्णा साहू उर्फ खाड्डु (उम्र 33 वर्ष), निवासी उमरकोट, उड़ीसा के कब्जे से 0.242 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 2,500 रुपए आंकी गई। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है और वाहन को जप्त कर लिया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में सायबर टीम सहित पुलिस के अन्य जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगाया केसर आम का पौधा

दंतेवाड़ा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान सर्किट हाऊस परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत केसर आम का पौधा लगाया। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमनसिंह ने आम एवं वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने नारियल का पौधा लगाया। इस अवसर पर सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप ने बादाम एवं विधायक श्री चैतराम अटामी द्वारा कटहल का पौधा लगाया गया। उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत लगातार पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में दंतेवाड़ा जिले में अब तक 12 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

नाबालिग ने अज्ञात कारणों के चलते घर में लगाई फांसी

जगदलपुर। जगदलपुर में बोधघाट थाना क्षेत्र के आड़ावाल में रहने वाले एक ट्रक चालक के नाबालिक बेटे ने शुक्रवार की सुबह अपने घर के किचन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटे को फंदे में लटके उसकी माँ ने पहले देखा, जिसके बाद आसपास के लोगों के साथ ही परिजनों को मामले की जानकारी दी, घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दिया, जहाँ शव को पीएम के लिए मेकाज ले जाया गया। मामले की जानकारी देते हुए बोधघाट थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि आड़ावाल खासपारा निवासी शशि कुर्रे का नाबालिक बेटा जो कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा था, पिता ट्रक चालक का काम करते है और सामान छोड़ने के लिए रायपुर गए हुए थे, अचानक आज सुबह जब नाबालिक सो के उठा तो उसकी माँ ने देखने के बाद अपने काम करने के लिए चली गई, तब तक नाबालिक ने किचन में लगे पंखे में फंदा बनाकर उसमें झूल गया। काम करके जब माँ किचन में आई तो उसने अपने नाबालिक बेटे को फंदे में लटका देख शोर मचाने लगी।

छत्तीसगढ़ का पहला अमृत सरोवर, सूखी धरती हुई हरी

धमतरी। धमतरी जिला प्रशासन ने कुरुद विकास खंड के कन्हारपुरी ग्राम पंचायत में मुरा तालाब का कायाकल्प किया है। इस तालाब का गहरीकरण करके करीब 9 एकड़ क्षेत्रफल में अमृत सरोवर विकसित किया गया है। जिससे भूजल रिचार्ज हुआ और आसपास की सूखी भूमि को खेती के लिए पानी मिला।जिससे जमीन उपजाऊ हो गई। गहरीकरण के पहले मुरा तालाब की जलधारण क्षमता 32,400 घन मीटर थी, जो अब बढ़कर 57,800 घन मीटर हो गई है। गहराई लगभग 10 फीट से बढ़कर 15 फीट हो गई है। गहरीकरण प्रक्रिया ने जल संरक्षण संरचना के कारण बोरवेल को रिचार्ज किया।

तालाब के पुनर्जीवित होने के बाद, लगभग 50 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। इससे कन्हारपुरी गांव के कई किसानों को लाभ हो रहा है। यह तालाब जून 2024 से

मानसूनी वर्षा का पानी रोक रहा है, तब से यह ग्रामीणों के लिए राहत का केंद्र बन चुका है।अब गांव के लोग तालाब की मदद से खेती किसानी और पशुपालन में तेजी से आगे आ रहे हैं। कभी दो एकड़ में सिमटा हुआ ये तालाब मौजूदा समय में ना सिर्फ बढ़कर नौ एकड़ का हो चुका है,बल्कि तालाब के गहरीकरण के कारण गांव के लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया गया था।जो गांव के लिए आय सृजन मॉडल बना। रेलवे ने भी की बड़ी मदद = इस तालाब के गहरीकरण में रेलवे का भी योगदान किसी से कम नहीं है। रेलवे को रायपुर से धमतरी तक ब्रॉड गेज लाइन के लिए ट्रैक विकसित करना था। जिसके लिए उन्होंने धमतरी जिला प्रशासन से संपर्क किया। रेलवे ट्रैक को कन्हारपुरी गांव से होकर गुजरना था।लिहाजा जिला प्रशासन ने रेलवे बोर्ड और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच समझौता कराया।जिससे मुरा तालाब से मिट्टी और लेटराइड निकालने की अनुमति मिली। तालाब से निकाली गई मिट्टी और लेटराइट के लिए रेलवे ने ग्राम पंचायत को 12 लाख 20 हजार की रॉयल्टी दी।जिसके बाद रेलवे ने मशीन की मदद से तालाब की खुदाई करवाई।

जिला परियोजना अधिकारी धर्म सिंह ने कहा रेलवे बोर्ड ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए कन्हारपुरी से निकाली गई मिट्टी और लेटराइट के बदले ग्राम पंचायत को लगभग 12 ।20 लाख रुपये की रॉयल्टी दी। पंचायत इस धनराशि का उपयोग गांव के विकास के लिए करेगी।मिट्टी के बदले इसकी रॉयल्टी राशि तालाब की मैन्युअल खुदाई और गहरीकरण में लगभग 30 लाख रुपए की लागत आती जो 12 लाख रुपए में पूरा हुई।

वहीं धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण पर बड़ा काम हो रहा है। इसी के तहत कन्हारपुरी गांव में तालाब को पुनर्जीवित किया गया है।नया तालाब विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, केंद्रीय भूजल बोर्ड की सर्वेक्षण रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि कुरुद विकास बेल्ट में चूना पत्थर की उपस्थिति के कारण पुनर्जीवित जल निकाय हैं।रिचार्ज बने रहने की संभावना है, बशर्ते मौसम की स्थिति भी अनुकूल रहे।

कुटुमसर गुफा देखने के लिए सैलानियों को करना होगा और इंतजार

जगदलपुर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटुमसर गुफा को देखने के शौकीन सैलानियों को इस साल थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हर साल 1 अक्टूबर को गुफा खोली जाती है, लेकिन इस बार इसे 10 अक्टूबर तक खोले जाने की संभावना है। क्योंकि गुफाओं में अभी पानी भरा हुआ है। इसे भी पढ़ें = गंगरेल बांध के किनारे मनाया जाएगा जल जगार उत्सव, कार्निवल, कॉफ्रेंस, प्रदर्शनी, सामुदायिक खेल से लेकर ड्रोन शो, ट्रेल रन जैसे होंगे कार्यक्रमज

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ चूड़ामणि सिंह ने कहा है कि गुफा में पानी और अन्य बाधाओं की वजह से इसे साफ किया जा रहा है। पानी के साथ-

साथ बारिश के मौसम में गुफाओं में झाड़ियां उग जाती है, जिसकी सफाई की जा रही है, ताकि सैलानियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही गुफा तक पहुंचने वाले रास्तों को भी ठीक किया जा रहा है।

कांगेर घाटी में कई गुफाएं हैं, लेकिन सैलानियों की सबसे पसंदीदा कुटुमसर गुफा है। इसे 1956 में डॉ। शंकर तिवारी ने उजागर किया था। पहले मशाल का उपयोग कर गुफा को देखा जाता था, लेकिन अब गाइड सोलर लाइटों का उपयोग करते हैं। आमतौर पर बस्तर की गुफाएं 15 जून तक ही देखी जा सकती हैं। क्योंकि उसके बाद बारिश शुरू होने से गुफाओं में पानी भरने लगता है।

कुटुमसर गुफा को भारत की सबसे गहरी गुफा माना जाता है जिसकी गहराई 60 से 120 फीट के बीच है और इसकी कुल लंबाई लगभग 4500 फीट है। इस गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा 'कर्ल्सवार ऑफ़ केव' अमेरिका से की जाती है जो इसकी महत्ता को और बढ़ाती है।

इस गुफा की खोज 1950 के दशक में भूगोल के प्रोफेसर डॉ। शंकर तिवारी ने कुछ स्थानीय आदिवासियों की मदद से की थी।

संक्षिप्त समाचार

राज्य महिला आयोग में पांच सदस्यों की नियुक्ति

रायपुर। राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग में पांच नए सदस्यों की नियुक्ति की है। जिनमें श्रीमती लक्ष्मी वर्मा,श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती ओजस्वी मंडावी, श्रीमती दीपिका सोरी व श्रीमती प्रियवंदा सिंह जूदेव शामिल हैं। सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो के लिए होगा। महिला व बाल विकास विभाग की संयुक्त सचिव डा.रेणुका श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।

छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने नेहरू राम निषाद

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आयोग में नियुक्ति का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद को बनाया गया है। इसका आदेश प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से जारी कर दिया गया है। नेहरू राम निषाद वर्तमान में निषाद बीजेपी मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। इसके अलावा धमतरी निषाद समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे धमतरी जिले के रहने वाले हैं। काफी लंबे समय से नेहरू राम निषाद पार्टी को लेकर सक्रिय हैं। बता दें कि इससे पहले भी राज्य शासन ने विभिन्न प्राधिकरणों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई थी।

लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा, पुराने एडमिट कार्ड नहीं होंगे मान्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यापमं की प्रयोगशाला तकनीशियन की परीक्षा स्थगित होने के बाद एक बार फिर आयोजित की गई है। ये परीक्षा दोबारा 6 अक्टूबर दिन रविवार को आयोजित की गई है। उच्च शिक्षा विभाग में 260 रिक्त पदों के लिए व्यापमं ये परीक्षा ले रहा है। जिसके लिए व्यापमं ने ऑनलाइन आवेदन मंगवाए थे। सीजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा पहले 29 सितंबर को आयोजित होनी थी। लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था। सीजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए 23 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। जिसके बाद अभ्यर्थियों को सेंटर आवंटित हुए थे। लेकिन अब फिर से परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं।इसलिए अभ्यर्थियों को दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। पुराने एडमिट कार्ड पर परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को तय समय से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र आने को कहा गया है। यदि कोई छात्र देरी से सेंटर पहुंचता है, तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।इसके लिए व्यापमं ने नोटिफिकेशन जारी किया है।

सामान्य सभा के चलते मोबाइल पर गेम खेल रहे थे अधिकारी, अध्यक्ष की चेतावनी

रायपुर। अधिकारी कितने जिम्मेदार होते हैं इसका एक उदाहरण रायपुर नगर निगम के महत्वपूर्ण आखिरी सामान्य सभा में शुक्रवार को देखने मिला जब एक अपर आयुक्त को मोबाइल पर गेम खेलते हुए अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने देख लिया। एक दो और अधिकारी ताशपत्ती और कैंडी क्रश जैसे गेम खेल रहे थे। अध्यक्ष दुबे ने कहा कि पद के साथ अपने कार्य दायित्व का ध्यान रखें,यह आपके और आपके भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। अध्यक्ष के तीखे तेवर देखकर कुछ देर के लिए पार्षद और अधिकारी भी सन्न रह गए।

मेट्रो ट्रेन पर गर्माया सदन, भाजपा पार्षदों ने एमओयू तख्ती के साथ किया हंगामा

रायपुर। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा के शुरू होने से पहले हंगामा शुरू हो गया। भाजपा पार्षद मेट्रो ट्रेन से जुड़े प्रश्नों को एजेंडा से हटाने के विरोध में 'जवाब दो' के नारे के साथ एमओयू का विशाल बोर्ड लेकर पहुँचे थे। रायपुर निगम की सात महीने बाद हुई सामान्य सभा भी हंगामाखेज रही। मेट्रो ट्रेन पर चर्चा की मांग करते हुए सभापति आसंदी के सामने पहुंचे भाजपा का पार्षद दल पहुंचा। हंगामे को देखते हुए सभापति ने दस मिनट के लिए स्थगित किया। सामान्य सभा के दोबारा शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने फिर से हंगामा मचाना शुरू कर दिया। भाजपा पार्षद महापौर एजाज ढेबर से मेट्रो रेल को लेकर किए गए एमओयू पर जवाब की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने वरिष्ठ पत्रकार नितिन चौबे के निधन पर किया गहरा दुख प्रकट

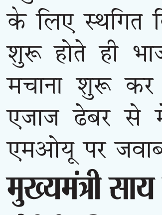

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री नितिन चौबे के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार श्री नितिन चौबे जी के निधन का समाचार बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। श्री नितिन चौबे जनतंत्र टी.व्ही. के छत्तीसगढ़ प्रमुख थे।

मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा में 167 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

दंतेवाड़ा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दंतेवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान जिले में 167 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों की लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें लोकार्पण के तहत जिला दन्तेवाड़ा के विकासखण्ड कुआकोण्डा में शासकीय उपाधि महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों हेतु 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य 272.450 लाख रू., दन्तेवाड़ा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण 99.000 लाख रू., 100 सीटर छात्रावास भवन का निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा 160.000 लाख रू., बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य विकासखण्ड-गीदम 453.000 लाख रू., शंकनी-डंकनी नदी तट पर घाट निर्माण 3659.700 लाख रू., 500 सीटर आवासीय विद्यालय कारली के भवन निर्माण कार्य विद्युतीकरण सहित वि.ख.-गीदम 487.150 लाख रू., एनीकट निर्माण कार्य कटेकल्याण पुजारी पारा डुमाम नदी पर 350.000 लाख रू., दुगेली एनीकट निर्माण कार्य 372.940 लाख रू., प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिन्दनार का निर्माण कार्य 75.000 लाख रू., उप स्वास्थ्य केन्द्र हिड़पाल का निर्माण कार्य 28.510 लाख रू. के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

इसी प्रकार भूमिपूजन के अन्तर्गत आस्था विद्या मंदिर किरन्दुल हेतु भवन निर्माण, कर्मचारी हेतु आवास, छात्रावास भवन सड़क नाली बाउंड्री निर्माण आदि 4219.000, जिला दन्तेवाड़ा के रानीबाग में भवन निवास के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण कार्य 326.570, मड़कामीरास में 50 सीटर आदिवासी प्री. मे. कन्या छात्रावास निर्माण कार्य 191.510, जंगमपाल में 50 सीटर कन्या आश्रम का निर्माण कार्य 162.760, बड़ेगुडरा में 100 सीटर आदिवासी पो. मै.कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य 288.590, मारजूम में 50 सीटर कन्या आश्रम का निर्माण कार्य 162.760, समेली में 100 सीटर आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य 191.510, पालनार में 100 सीटर आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य 288.590, ग्राम जावंगा में स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य 221.040, जोगिंग ट्रैक एवं बाउंड्रीबॉल निर्माण कार्य 47.130, सामुदायिक भवन गीदम जावंगा में पार्क एवं ट्यूबवेल निर्माण कार्य 49.510, आदिवासी बालक आश्रम बोदली में कार्य 162.760, आदिवासी बालक आश्रम समेली में कार्य 162.760, आदिवासी बालक आश्रम नहाड़ी में कार्य 162.760, आदिवासी बालक आश्रम बुरगुग 162.760, आदिवासी बालक आश्रम पोटाली 162.760, आदिवासी बालक आश्रम कौरगांव 162.760 आदिवासी बालक आश्रम मुस्तलनार 162.760, आदिवासी बालक आश्रम गुमलनार 162.760 आदिवासी पो. मै. बालक छात्रावास गीदम 191.510, आदिवासी नवीन पो. मै. बालक छात्रावास गीदम 191.510, आदिवासी पो. मै. बालक छात्रावास कुआकोण्डा 191.510, आदिवासी पो.मे. बालक छात्रावास कासोली 191.510, आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास कासोली 191.510, आदिवासी पो. मै. बालक छात्रावास दन्तेवाड़ा 191.510, आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास दन्तेवाड़ा 191.510, कैडियापारा एनीकट (ग्राम पंचायत भूसारास) निर्माण कार्य 260.460, फरसपाल जलाशय योजना का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य 255.770, चेक डेम निर्माण कार्य ग्राम झिरका पण्डेवार 49.990, झोडियाबाड़म नदी पर एनीकट निर्माण कार्य 390.310, कामालूर से बासनपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण 18.450, आर. सी. सी. स्लेब पुलिया निर्माण 03 स्पान 06 मी. स्पान बालूद से कुआपारा 49.560, पुलिया निर्माण कामालुर से बासनपुर आर. डी. 4. 05 मी. 41.300, आर. सी. सी. स्लेब पुलिया निर्माण 06 मी. स्पान बालूद से मंझारपारा 25.180, पुलिया निर्माण बालूद से टोटापारा मार्ग 30.160, डंकनी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य कि. मी. पोन्दुम से दाबपाल मार्ग पर 445.700, जिला दन्तेवाड़ा के ग्रामीण महिला एवं युवाओं के लिये आर्थिक अवसरों को उप्रेरित करने के लिये युवा हब संचालन कार्य 59.800, ग्राम पंचायत नहाड़ी के आश्रित ग्राम मुलेर में विद्युतीकरण कार्य 345.000 के कार्य शामिल हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमनसिंह और वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप, विधायक दंतेवाड़ा श्री चैतराम अटामी, राज्य महिला आयोग के सदस्य श्रीमती ओजस्वी मण्डावी, डीआईजी श्री कमलोचन कश्यप, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, एसपी श्री गौरव राय तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों मौजूद रहे।

जशपुर के विकास को मिल रही नई उड़ान, तीव्र गति से हो रहा विकास कार्य

6 महीनों में लोक निर्माण विभाग के 113.19 करोड़ रुपयों की 43 सड़क निर्माण कार्यों की मिली स्वीकृति

रायपुर। जशपुर जिले के विकास को नई उड़ान दिलाने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर नई विकास परियोजनाओं का आगाज हो रहा है। जिसके द्वारा जिले के विकास को गति मिल रही है। पिछले 06 माह में लोक निर्माण विभाग की 113.19 करोड़ रुपयों की 43 सड़क निर्माण परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है।

जशपुर जिले के सभी विकासखंडों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए मुहिम चलाई जा रही है ताकि जिले के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं की पहुंच को बढ़ाया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाए। इसके लिए आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर उनके लिए तीव्र गति से तकनीकी विश्लेषण द्वारा डीपीआर निर्माण कर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। जिसका परिणाम है कि विगत 06 माह में 43 सड़क निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के साथ निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय की मंशानुरूप सभी सड़क निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कर आगामी 01 वर्ष में सभी को पूर्ण कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया हैं।

लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार के पत्थलगांव के अंतर्गत 73.30 करोड़ रुपयों के 25 सड़क मार्गों का निर्माण किया जाना है। जिसमें 10.94 करोड़ की लागत के एन.एच.43 से बिच्छीकानी ढुढरूपारा से जमरगी तक 8 किमी सड़क मार्ग, 7.98 करोड़ रूपए लागत के बगीया से सूजीबहार तक के 8.70 किमी सड़क मार्ग, 5.57 करोड़ रूपए लागत के लैलूंगा, कोतबा से लवाकेरा तक के 5.18 किमी सड़क मार्ग, 4.28 करोड़ लागत के 3.5 किमी के कांसांबेल मुसकुटी तक सड़क मार्ग, 4.03 करोड़ रूपए लागत के बाबूसाजबहार से गोलीडीह नदी तक सड़क मार्ग, 3 करोड़ रूपए लागत के 1.2 किमी के करजटोली से रजौटी तक सड़क मार्ग सहित 25 सड़क मार्गों का निर्माण कराया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के जशपुर के कार्यपालन अभियंता श्री विरेन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि जशपुर में 39.89 करोड़ रुपयों के 18 सड़क मार्गों का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिसमें 3.39 करोड़ लागत के चांडीडांड हत्ता हल्काटोली तक के 2.36 किमी सड़क मार्ग, 4.75 करोड़ लागत के एस.एच 17 मुख्य मार्ग से ढोगाअम्बा जामचुआ तक 3.26 किमी सड़क मार्ग, 3.6 करोड़ रूपए लागत के बनकोम्बों से घटमुंडा तक के 3.4 किमी सड़क मार्ग, 2.57 करोड़ रूपए लागत के बालाछापर आरा सकरडेगा से छोटाबनई तक के 2.4 किमी सड़क मार्ग, 2.45 करोड़ रूपए लागत के एन.एच. 43 खड़सा से कोमड़ो तक के 1.94 किमी सड़क मार्ग, 2.38 करोड़ रूपए लागत के भुड़केला से लवानदी पुल तक के 2.10 किमी सड़क मार्ग, 2.33 करोड़ रूपए लागत के खरवाटोली से बांधाटोली तक के 2 किमी सड़क मार्ग, 2.25 करोड़ रूपए लागत के बालाछापर आरा सकरडेगा से कारीताला तक के 2 किमी सड़क मार्ग, 2.29 करोड़ रूपए लागत के बहराखैर से जुड़वाईन तक के 1.63 किमी सड़क मार्ग सहित 18 मार्गों का निर्माण कराया जाएगा।

खेल मैदान का विधायक ने किया भूमिपूजन, स्वेच्छानुदान से दिए 11 लाख

रायपुर। बाल आश्रम परिसर में श्रीमती पी.जी. डागा कन्या महाविद्यालय के राष्ट्रीय विद्यालय, बाल आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में विधायक पुरन्दर मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में खेल मैदान का भूमिपूजन हुआ। खेल मैदान में जिम, बॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो, टेबल टेनिस आदि खेलने खेल मैदान का निर्माण होगा इस कार्य हेतु पुरन्दर मिश्रा ने स्वेच्छानुदान से 11 लाख रूपये देने की घोषणा की। अपने उद्बोधन में श्री मिश्रा ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को नशा छोडने का प्रचार प्रसार करने एवं मोबाइल का उपयोग कम से कम करने का अनुरोध किया। जो आपके परिसर में खेल मैदान तैयार होगा उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।

इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अजय तिवारी, देवीचन्द श्रीश्रीमाल, गोकुल दास डागा, नरेश गुप्ता, सुरेश शुक्ला, गोवर्धन दास डागा, राजकिशोर नत्यानी, दीपक दुबे, पी.आर. गोलछा, मदन लाल तालेड़ा, आरके गुप्ता, हरिवल्लभ अग्रवाल, रूपचंद श्रीश्रीमाल, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. श्रीमती संगिता घई, विद्यालय के प्राचार्य पीडी दीवान, श्रीमती हेमलता रेड्डी के साथ ही महाविद्यालय के प्राध्यापक, विद्यालय के प्राध्यापक, संस्थाओं के कर्मचारी एवं महाविद्यालय के छात्राए उपस्थित थी। यह जानकारी डॉ. संगीता घई ने दी।

छसपा का राज्योत्सव 23 से

31 की शाम को राजधानी में जगह-जगह करेंगे आतिशबाजी

रायपुर। सबसे पहला राज्योत्सव राज्य आंदोलनकारी छसपा ने 1 नवंबर 2000 को मनाया था जिसका अनुसरण राज्य सरकार ने दूसरे वर्ष 2001 से प्रारंभ किया। राज्य आंदोलनकारियों ने राज्योत्सव का क्रम प्रतिवर्ष मनाते आ रहे है और इस राज्योत्सव का नाम रजत जयंती छत्तीसगढ़ राज्योत्सव दिया है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों का 25वां आयोजन है। राज्य आंदोलनकारी के अध्यक्ष अनिल दुबे, जी.पी. चंद्राकर, जागेश्वर प्रसाद व वेगेन्द्र सोनबेर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि राजधानी में 23 अक्टूबर को आयोजन का शंखनाद होगा जिसमें तीन पाली का कार्यक्रम आयोजित है। पहला राजधानी में छत्तीसगढ़ के सैकड़ों कलाकार सड़कों पर छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करेंगे। दूसरे पाली में सभी राज्य आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ स्तर पर साल भर आयोजन कर बनायेंगे कार्यक्रम, रथ यात्रा के प्रभारी के साथ चलचित्र प्रदर्शन की रूपरेखा होगी तय। तीसरे पाली में शाम 7 बजे से छत्तीसगढ़ी फिल्म स्टार सुनील तिवारी की टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। यह कार्यक्रम साहू काम्पलेक्स धर्मशाला टिकरापारा में आयोजित किया गया है। चूंकि 31 अक्टूबर की शाम को 7 बजे से राज्य आंदोलनकारी राजधानी रायपुर के 10 जगहों पर आतिशबाजी करके राज्योत्सव मनाएगा।

बोरियाखुर्द में 55 फीट का रावण व 40-40 फीट के मेघनाथ और कुंभकरण का होगा दहन

रायपुर। बोरियाखुर्द खेल मैदान में आयोजित होने वाले दशहरा उत्सव की तैयारी में मोहल्ले के लोग अभी से जुट गए है। दशहरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष गजेन्द्र तिवारी ने बताया कि इस वर्ष 55 फीट का रावण, 40-40 फीट का मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले का दहण किया जाएगा, जिसे कारीगर अभी से बनाने में जुट गए है। दशहरा समिति के मीडिया प्रभारी एवं प्रचार प्रसार के विजय वर्मा व फलेश्वर साहू ने बताया कि 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बच्चों एवं युवाओं द्वारा पतंगबाजी के बाद स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद शाम को 7 बजे रावण दहन किया जाएगा इससे पहले भव्य आतिशबाजी की जाएगी। रात्रि 8 बजे से छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अंजोर लोक कला मंच के गरिमा स्वर्णा दिवाकर के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पूर्व गुरुवार को आयोजन स्थल पर भूमि पूजन कर तैयारियां प्रारंभ की गई। इस अवसर पर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष लच्छूराम निषाद, उपाध्यक्ष रमेश कुमार नंदे, दूज राम साहू, सचिव रुद्र कुमार साहू, कोषाध्यक्ष कोमल साहू, एनके शुक्ला, लेखराम साहू, संदीप साहू, गोपाल साहू, रोशन लाल साहू, धनराज सतपुते, मोहित सेन समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

सिंचाई पानी के प्रवाह में रुकावट पैदा कर रहे अवैध मछली पकडने वाले, कार्यवाही हेतु ज्ञापन

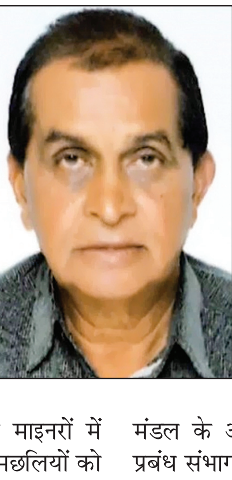

रायपुर। गंगरेल बांध से सिंचाई हेतु छोड़े गये पानी के अबाध प्रवाह में अवैध रूप से मछली पकडने वाले रुकावट डाल सिंचाई समस्या पैदा कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने रायपुर जिला जल उपभोक्ता संस्था संघ के अध्यक्ष रहे भूपेन्द्र शर्मा ने महानदी जलाशय परियोजना के मुख्य अभियंता कुबेर सिंह गुरुवर को व्हाट्स ऐप के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में बताया गया है कि गंगरेल के नहरों, वितरक शाखाओं व माइनरों में प्रवाहित हो रहे पानी के साथ आने वाले मछलियों को पकडने कतिपय विध्नसंतोषी तत्व इन माइनरों व वितरक शाखाओं के गेट को गिरा खासकर रात्रि में जाल डाल अवैध रूप से मछली पकड़ते हैं। इनके द्वारा गेट गिरा दिये जाने से पानी का प्रवाह थम जाता है जिसके चलते निरंतर सिंचाई में बाधा उत्पन्न हो जाती है और नये सिरे से खेतों में पानी पहुंचाने में समय लगता है। ज्ञापन में इन विध्नसंतोषी तत्वों द्वारा माइनरों व वितरक शाखाओं के गेट की डुप्लीकेट चाबी बनवा यह कार्य करने की आंशका व्यक्त करते हुये ऐसे तत्वों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन में सर्वप्रथम इन तत्वों को चेतावनी देने ग्राम कोटवारों के माध्यम से तुरंत प्राथमिकता के आधार पर मुनादी कराने और बाज न आने पर इनके द्वारा लगाये गये जाल को जप्त कर सिंचाई अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने के साथ - साथ इनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत भी पुलिसिया कार्यवाही सुनिश्चित कराने आवश्यक पहल का आग्रह किया गया है। इसकी जानकारी महानदी सिंचाई मंडल के अधीक्षण अभियंता एस के सहारे, जल प्रबंध संभाग क्रमांक के कार्यपालन अभियंता ललित रावटे व बगोली सिंचाई उपसंभाग के अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद पाल को देते हुये अपने कमांड वाले प्रशासनिक क्षेत्र के ग्रामों में फौरी कदम उठाने का आग्रह किया गया है। इधर श्री शर्मा ने जानकारी दी है कि सिंचाई पंचायतों के अस्तित्व समाप्त होने तक इन माइनरों व वितरक शाखाओं को मछली पकडने इस शर्त के साथ नीलाम किया जाता था कि वे पानी के प्रवाह को सुनिश्चित बनाये रखेंगे पर नीलामी की कार्यवाही बंद होने के बाद से यह समस्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है।

प्रदेश के बोर्ड कक्षाओं के 40 हजार बच्चों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन

■ माशिमं सचिव ने कहा- पालकों को नहीं, स्कूलों को देना होगा शुल्क

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बोर्ड कक्षाओं में पढ़ रहे लगभग 40 हजार बच्चों का भविष्य दांव पर है। 587 स्कूल ने अब तक एक भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसके अलावा 553 स्कूलों में किसी में 5 तो किसी में 10 बच्चों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं हुआ है। पंजीयन ना होने पर यह बच्चे बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इन स्कूलों को नोटिस जारी करने के बाद भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि प्रदेश में लगभग 7 हजार स्कूलों में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें से सीजीबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 1140 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन में देर की है, जिनमें से 587 स्कूल ने अब तक एक भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वहीं बाकी स्कूलों में किसी में 4 तो किसी में दस बच्चों का पंजीयन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाला लेट फीस बच्चों के हिसाब से नहीं बल्कि प्रत्येक स्कूल प्रबंधन को देना होगा। इस शुल्क बच्चों को नहीं बल्कि स्कूलों को देना होगा। प्रतिदिन लेट के हिसाब से एक हजार रुपये तय किया गया है। उन्होंने बताया कि, रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 18 जून से लेकर 16 अगस्त तक आवेदन करने का समय दिया गया था। इस अवधि को बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक का समय बढ़ाया गया। शिक्षा मण्डल के पोर्टल के माध्यम से जानकारी स्कूलों तक पहुंचाई गई। इसके बाद मैसेज के माध्यम से स्कूलों को सूचित किया गया फिर स्कूलों को लेटर भी भेजा गया था। इसके बावजूद भी इन लापरवाह स्कूलों ने बच्चों का पंजियन (रजिस्ट्रेशन) नहीं कराया है। इन लापरवाह स्कूलों को लेट फीस के साथ एक और मौका दिया गया है। अब 6 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 31 अगस्त के बाद से प्रति दिन 1 हजार रुपये लेट फीस जमा करना होगा। शिक्षा कार्य से जुड़े लोगों ने बताया कि बच्चों के पालकों से पूरे शिक्षा सत्र के तमाम फीस एक साथ ले ली जाती है.

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 07782-222336, (कार्या.) फैक्स क्रं. 225777, ई-मेल spofficejdr@gmail.com

क्रमांकः-पु.अ./बस्तर/एसी/पीएचक्यू/ 2660-ए/2024 **दिनांक- 23/09/2024**

// अल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना//

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित निर्माण कार्य के लिए मुहरबंद निविदायें प्रपत्र-अ में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा 01. 01.2015 (भवन) एवं निविदा जारी दिनांक तक संशोधित दर अनुसूची के आधार पर लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/छ.ग. गृह निर्माण मण्डल/ग्रमीण यांत्रिकी सेवा/सिंचाई विभाग में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दो लिफाफा पद्धति, जिसमें एक अमानत राशि व दूसरा निविदा प्रपत्र का लिफाफा होगा, निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित की जाती है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर, जगदलपुर में निविदाओं को उपस्थित निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी। उक्त तिथि को अपरिहार्य परिस्थिति में निविदा संबंधी कार्यवाही अगले कार्य दिवस को की जावेगी। **(1) निविदा प्रपत्र का मूल्य 750/- निर्धारित। (2) ठेके की श्रेणी डी एवं उच्च श्रेणी रहेगी निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि- 09/10/2024 के 05.00 बजे तक। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि- 11/10/2024 के 04.00 बजे तक। निविदा खोले जाने की तिथि- 11/10/2024 के संध्या 05.00 बजे।**

क्र.	कार्य का नाम एवं कार्यस्थल	कार्यावधि	लागत	धरोहर राशि
1.	Maintenance of CAPF Interogation Complex, Jagdalpur	03 माह	14.65 लाख	11000/-
2.	रक्षित केन्द्र, जगदलपुर में वाहन धोने का रैम्प निर्माण कार्य	03 माह	6.23 लाख	5000/-
3.	महिला बैरक जगदलपुर में टॉयलेट/बाथरूम निर्माण कार्य	03 माह	5.56 लाख	5000/-
4.	थाना दरभा में टॉयलेट/बाथरूम मय ओपन वाटर टैंक निर्माण कार्य	03 माह	9.45 लाख	7100/-

निविदा से संबंधित अन्य जानकारी हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जगदलपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

नोटः- निविदा फार्म प्राप्ति हेतु कार्यालय में उपस्थित होने पर आवश्यक समस्त दस्तावेज अपने साथ लेकर उपस्थित होवें।

पुलिस अधीक्षक
जिला-बस्तर, जगदलपुर

जी-242502910/2

जम्मू-कश्मीर में चुनाव का पूरा होना एक ऐतिहासिक पड़ाव

अरविंद मोहन

तो जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव सम्पन्न हो गए और यह पुराना जम्मू-कश्मीर नहीं है। क्योंकि इसके चुनाव पर देश दुनिया की नजर लगी थी और लगी हुई है। पर शांतिपूर्ण ढंग से और एकदम नई हवा के झौंके के बीच चुनाव का पूरा हो जाना भी एक ऐतिहासिक पड़ाव है। अब सरकार के गठन वाला दौर भी कुछ नई दिलचस्प स्थितियों को जन्म दे सकता है और भाजपा तथा देश की राजनीति पर असर डालेगा इसलिए उस पर भी देश और दुनिया की नजर होगी। धारा 370 की समाप्ति, इस सीमांत प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटना और फिर जम्मू-कश्मीर विधान सभा सीटों के पुनर्गठन ने चुनाव को ज्यादा दिलचस्प बना दिया था। जब से कश्मीर ने भारत में विलय को स्वीकार किया था तब से 370 ही इस जुड़ाव का आधार माना जाता था। पर धीरे-धीरे उसे भी एक तमाशा बना दिया गया था और अपनी राजनीतिक नाकामियों या कमजोरियों को ढंकने के लिए उसका इस्तेमाल होने लगा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ/भारतीय जनता पार्टी का एक समांतर विमर्श लगातार चलता रहा और उससे देश भर में वह अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती गई लेकिन खुद कश्मीर में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत से लेकर काफी कुछ हुआ था। उस लिहाज से यह चुनाव एक प्रभावी और आम विमर्श (धारा 370 के पक्ष वाला) के मुकाबले पहली बार संघीय विमर्श के ऊपर आने के बाद का चुनाव था। लेकिन विधानसभा चुनाव से पूर्व हुए लोकसभा चुनाव में इस पहलू ने दम तोड़-सा दिया क्योंकि भाजपा ने घाटी में अपने उम्मीदवार उतारे ही नहीं और बहुत साफ ढंग से गठबंधन करके किसी और दल या निर्दलीय को समर्थन भी नहीं दिया। उसका समर्थन किन लोगों को रहा इसके इशारे बहुत साफ थे। लेकिन बाकी ही क्यों भाजपा के लोग भी तब निराश हुए जब इस बार के चुनाव में भी पार्टी ने घाटी की ज्यादातर सीटें न लडऩे का फैसला किया और निर्दलीय तथा छोटे दलों से गठबंधन को लेकर भी कोई साफ राजनीति नहीं की। इंडिया गठबंधन को भी 3 बड़ी पार्टियों को संभालकर चुनाव लडऩे में दिक्कत हुई और न सिर्फ महबूबा मुफ्ती की पार्टी पी.डी.पी. अलग होकर लडऩे उतरी बल्कि कांग्रेस और नैशनल कांफ्रैंस में गठबंधन रहने के बावजूद अनेक सीटों पर 'दोस्ताना' मुकाबला हुआ। तब भी इसी गठजोड़ को आगे माना जाता रहा। यह जरूर हुआ कि आखिर तक आते-आते और चुनाव के मुख्य रूप से जम्मू क्षेत्र में पहुंचने पर इस गठजोड़ को ज्यादा मुश्किल आने की बात हवा में आने लगी। जिस निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद पर भाजपा का आदमी होने की मोहर कैसे लगती गई, उनका मानना था कि अगर उनको एक हफ्ता पहले पैरोल मिल जाती तो वे राज्य में सरकार बनाने/बनवाने की स्थिति में होते। राशिद इंजीनियर की बात अपनी जगह है और पिछले चुनाव में जेल से ही उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा मतों से हराने का रिकार्ड उनकी ताकत को बताता है लेकिन बीच चुनाव में उनको पैरोल मिलने से उनको और अनेक निर्दलीयों/छोटे दल वालों को भाजपा का एजैंट कहे जाने का स्वर चुनाव के दौरान प्रबल हुआ है और उनके लिए इस छापे को छुड़ाना ही बहुत मेहनत का काम रहा। जम्मू इलाके में भाजपा काफी मजबूत रही है और पुनर्गठन के क्रम में जम्मू क्षेत्र की सीटें घाटी से ज्यादा हो गई हैं। अब जनप्रतिनिधियों, सत्ता के सूत्रधार राजनेताओं और कई बार अघोषित रूप से होने वाला थैलीशाहों का खेल शुरू होगा। और कश्मीर का मामला हो तो इसमें बाहरी शक्तियां भी छोटी बड़ी भूमिका निभाने पहुंच जाती हैं भले उनकी ज्यादा चले या न चले। भाजपा की तरफ से और मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस चुनाव में बहुत कुछ अपूर्व और रिकार्ड कहा गया पर अभी मतदान में भी 2014 का रिकार्ड मुंह चिढ़ा रहा है। इस बार ज्यादा शांत और भागीदारी वाला चुनाव हुआ जिसे एक उपलब्धि मान सकते है। न बायकाट का आह्वान हुआ न बम फूटे, न पत्थरबाजी हुई न मतदान केंद्र पर ताबूत रखा गया और न हाथ काटने की धमकी सुनाई दी। अब इंतजार कीजिए सरकार बनने-बनाने वाले दौर का।

अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करता आरएसएस

प्रह्लाद सबनानी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवकों एवं भारतीय समाज के लिए संघ के अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करना एक गर्व का विषय हो सकता है। संघ के स्वयंसेवक समाज में अपना सेवा कार्य पूरी प्रामाणिकता से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से करते रहते हैं। वरना, भारत सहित पूरे विश्व में आज ऐसा माहौल बन गया है कि कुछ संगठन जो समाज में सेवा कार्य करते तो बहुत थोड़ा है परंतु उस कार्य का बहुत अधिक प्रचार प्रसार करते हैं। इसके ठीक विपरीत संघ के स्वयंसेवक चुपचाप समाज में अपने ईश्वरीय कार्य को सम्पादित करते रहते हैं, कई बार तो संघ के पदाधिकारियों को भी इस बात का आभास नहीं हो पाता है कि हमारे संघ के स्वयंसेवकों ने समाज में कोई विशेष सेवा कार्य सम्पन्न किया है। दरअसल, संघ के स्वयंसेवकों को यह संस्कार संघ की शाखा में प्रदान किए जाते हैं। और, इसी प्रकार की कई अन्य विशेषताओं के चलते, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे विश्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन कहा जाने लगा है।

भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा संगठन रहा होगा जो अपनी स्थापना के समय से ही निर्धारित किए गए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना उस समय हुई थी, जब अंग्रेजों की दासता में भारतीय संस्कृति का सर्वनाश हो रहा था। इससे व्यथित होकर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयादशमी के पावन अवसर पर वर्ष 1925 में की थी। मार्च 2024 में संघ की नागपुर में आयोजित प्रतिनिधि सभा में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 922 जिलों, 6597 खंडों एवं 27,720 मंडलों में 73,117 दैनिक शाखाएं हैं, प्रत्येक मंडल में 12 से 15 गांव शामिल हैं। समाज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में संघ की प्रेरणा से 40 से अधिक विभिन्न संगठन अपना कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण तथा हिंदू समाज को संगठित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। देश में राजनैतिक कारणों के चलते संघ पर तीन बार प्रतिबंध भी लगाया गया है- वर्ष 1948, वर्ष 1975 एवं वर्ष 1992 में - परंतु तीनों ही बार संघ पहिले से भी अधिक सशक्त होकर

भारतीय समाज के बीच उभरा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू शब्द की व्याख्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में करता है जो किसी भी तरह से (पश्चिमी) धार्मिक अवधारणा के समान नहीं है। इसकी विचारधारा और मिशन का जीवंत सम्बंध स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, बाल गंगाधर तिलक और बी सी पाल जैसे हिंदू विचारकों के दर्शन से हैं। विवेकानंद ने यह महसूस किया था कि एक सही अर्थों में हिंदू संगठन अत्यंत आवश्यक है जो हिंदुओं को परस्पर सहयोग और सराहना का भाव सिखाए।

स्वामी विवेकानंद के इस विचार को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने व्यवहार में बदल दिया। उनका मानना था कि हिंदुओं को एक ऐसे कार्य दर्शन की आवश्यकता है जो इतिहास और संस्कृति पर आधारित हो, जो उनके अतीत का हिस्सा हो और जिसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी हो। संघ की शाखाएं स्व के भाव को परिशुद्ध कर उसे एक बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय हित की भावना में मिला देती हैं। वस्तुत: यह कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने व हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा कर राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के उद्देश्य से डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की। आज संघ का केवल एक ही ध्येय है कि भारत को पुन: विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना।

संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी की दृष्टि हिंदू संस्कृति के बारे में बहुत स्पष्ट थी एवं वे इसे भारत में पुन: प्रतिष्ठित कराना चाहते थे। डॉक्टर साहब के अनुसार, हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान का प्राण है। अतएव हिंदुस्तान का संरक्षण करना हो तो हिंदू संस्कृति का संरक्षण करना हमारा पहला कर्त्तव्य हो जाता है। हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति ही नष्ट होने वाली हो तो, हिंदू समाज का नामोनिशान हिंदुस्तान से मिटने वाला हो, तो फिर शेष जमीन के टुकड़े को हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि राष्ट्र जमीन के टुकड़े का नाम तो नहीं हैज्ज यह बात एकदम सत्य है। फिर भी हिंदू धर्म तथा हिंदू संस्कृति की सुरक्षा एवं प्रतिदिन विधर्मियों द्वारा हिंदू समाज पर हो रहे विनाशकरी हमलों को कांग्रेस द्वारा दुरलक्षित किया जा रहा है, इसलिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता है।

जिस खंडकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी वह मुस्लिम तुष्टिकरण का काल था। वर्ष 1920 में देश में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मुसलमानों का नेतृत्व मुल्ला-मौलवियों के हाथों में था। इस खंडकाल में मुसलमानों ने देश में अनेक दंगे किए। केरल में मोपला मुसलमानों ने विद्रोह किया। उसमें हजारों हिंदू मारे गए। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के कारण हिंदुओं में अत्यंत असुरक्षिता की भावना फैली थी। हिंदू संगठित हुए बिना मुस्लिम आक्राताओं के सामने टिक नहीं सकेंगे, यह विचार अनेक लोगों ने प्रस्तुत किया और इस प्रकार हिंदू हितों के रक्षार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। संघ के प्रयासों से भारत में विस्मृत राष्ट्रभाव का पुनर्जागरण प्रारम्भ हुआ। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के आधार पर सार्वभौम हिंदुत्व का प्रचार किया। आधुनिक भारत के अंतरराष्ट्रीय शंकराचार्य के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया जा सकता है। उनके प्रयासों से हिंदू धर्म का न केवल उद्धार हुआ, अपती हिंदू समाज को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित भी किया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, राजनारायण बोस, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, योगी अरविंद, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जैसे हिंदू हितचिंतकों ने विश्व के समक्ष यह संदेश दिया कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय एकता का आधार हिंदू धर्म है और स्वयं हिंदू एक धर्म प्रधान एवं प्रकृति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधार जीवन पद्धति है।

पश्चिमी देशों में जीवन के लक्ष्य का सदैव अभाव रहा है। भौतिक सुख-समृद्धि ही जीवन का मानक बन गया था। इसलिए पश्चिमी देश असंवेदनशील हो गए थे। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद जैसी वैचारिकी इस भौतिकवादी पृष्ठभूमि की उपज रही है। भौतिकता की अंधी दौड़ ने अंतत: नाजीवादी, फासीवाद एवं साम्यवाद जैसे विचारों को जन्म देकर पश्चिमी देशों को महायुद्धों की विनाशलीला में झोंक दिया था। स्वामी विवेकानंद जैसे हिंदू चिंतकों द्वारा पश्चिमी देशों में हिंदुत्व के आदर्शों को प्रस्थापित कर उन्हें अंधकार से अलग करने का प्रयास किया गया था। हिंदू आदर्शों का यदि अनुपालन किया जाता तो सम्भवत- मानवीय विनाश के उन दृश्यों को रोका जा सकता था जो विश्व मानव की छाती पर एक भीषण घटित दुर्घटना के चोट के चिन्ह रूप में विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद ने जीवन जीने के लक्ष्य एवं मानव संस्कृति के मूल रहस्यों को पश्चिमी समाज के समक्ष उद्घाटित किया था। स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से पश्चिमी समाज में हिंदुत्व के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ था और लोग हिंदू संस्कृति के मूल रहस्यों को जानने के लिए आकर्षित हुए। स्वामी विवेकानंद को हिंदू राष्ट्रीयता का विश्व में प्रथम उद्घोषक कहा जा सकता है। उन्होंने विश्व के समक्ष भारत की मूल्यवान आध्यात्मिक धरोहर को प्रतिष्ठित किया तथा हिंदू धर्म के मूल रहस्यों से विश्व को अवगत कराया। स्वामी रामतीर्थ, महर्षि दयानंद, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, एम एस गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगढ़ी जैसे चिंतकों ने हिंदुओं को चिंतन की एक नयी शैली एवं विधा से सुसज्जित कर हिंदुत्व के पुनरुत्थान का सार्थक प्रयास किया। उक्त हिन्दू चिंतकों ने विश्व समुदाय में हिन्दुत्व के प्रति फैले भ्रम को न केवल दूर करने का प्रयास किया, अपितु हिन्दुस्तान में सनातन संस्कृति के प्रति जो वैषम्यतापूर्ण विचारधाराएं बलवती हो रही थीं उन्हें भी प्रतिबन्धित करने का प्रयास किया।

मुगलकाल एवं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हिन्दू लोक जीवन विखंडित हो गया था। हिन्दू धर्म के मूल रहस्यों से अनभिज्ञ आक्रांताओं ने न केवल वैयक्तिक अधिकारों का हनन किया अपितु हिन्दू धर्म के मूल ग्रंथों को भी नष्ट कर दिया। 1000 वर्षो तक सनातन संस्कृति विधर्मियों के प्रहार को झेलती हुई लगभग मृतप्राय बना दी गई थी। अब आवश्यकता है कि मूल्य परक हिन्दू जीवन पद्धति जिससे न केवल मानव अपितु प्रकृति एवं जीव-जन्तु जगत का भी उत्थान सम्भव है, उसे पुन: प्रतिष्ठित किया जाए। वस्तुत: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज भी लक्ष्य हिंदुओं को जाति, क्षेत्र और भाषा के कृत्रिम विभाजन के चलते उत्पन्न सामाजिक सांस्कृतिक विरोधभासों से उबारना है।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

उपनिषद्-ग्रंथ

गतांक से आगे...

(61) स यथाऽऽद्वैधाग्नेरव्याहितात् पृथग्धूमा विनिश्च- रन्ति एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्, यदृग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहास- पुराणम्। (बृहदारण्यक 2 ।4 ।11)

अर्थात् - (पं0 राजाराम प्रोफेसर का भाषार्थ) जो आग गोली लकड़ियों से जलाई है जैसा कि उससे अलग घूम (के बादल) बाहर निकलते हैं इसी प्रकार हे मैत्रेयी, इस बड़ी सत्ता से यह बाहर की ओर साँस लिया गया है। जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वाङ्गिरस पुराण हैं इसीके ही यह सांस लिए हुए हैं।

(62) नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेद अथर्वण- श्चतुर्थ इतिहासपुराण: पञ्चमो वेदानाँ वेद:

अर्थात् - ऋग्वेद यजुर्वेद असामवेद और चौथा अथर्ववेद तथा पांचवां वेदों का वेद इतिहास पुराण यह सब ब्रह्मरूप हैं इसकी उपासना कर!

(63) वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञायति यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्। (छान्दोग्य 7 ।2 ।1)

अर्थात् - ईश्वर की वाणी ही ऋग्वेदादि चार वेदों और इतिहास पुराण नामक पांचवें वेद को विज्ञापित करती है।

उपर्युक्त उपनिषद्-ग्रन्थों के प्रमाणों में पुराणों को बार-बार पांचवें वेद के नाम से स्मरण किया है। उपनिषद् काल में वर्तमान रूपापन्न अठारह पुराण न थे बल्कि इन सब का मौलिक तत्त्वभूत एक ही ग्रन्थ था, जो वेदों की भांति गुरु-शिष्य-सम्प्रदाय द्वारा पढ़ा जाता था । इस रहस्य का पूरा विवरण परम्पराध्याय में लिखा जायगा । यहाँ केवल एतावन्मात्र समझ लेना आवश्यक होगा कि उक्त प्रमाणों में जो एक वचन का निर्देश किया गया है वह उसी एकत्वसंख्यावछिन्न ग्रन्थ का संकेत करता है। **क्रमश: ...**

विश्व शिक्षक दिवस

ललित गर्ग

दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति होती है- शिक्षक, उनकी प्रासंगिकता, अनिवार्यता और उपयोगिता कभी समाप्त नहीं हो सकती। शिक्षकों के कंधों पर ही उन्नत विश्व के निर्माण का गुरुत्तर दायित्व होता है। यदि इस दायित्व में थोड़ी-सी भूल रह जाती है तो समाज, राष्ट्र एवं विश्व के निर्माण की नींव खोखली रह जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण इकाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विश्व शिक्षक दिवस की शुरूआत 5 अक्टूबर, 1994 को गयी थी। इसका उद्देश्य विश्वभर के शिक्षकों द्वारा विश्व के लगभग दो अरब पचास करोड़ बच्चों के जीवन निर्माण में दिये जा रहे महत्वपूर्ण योगदान पर विचार-विमर्श

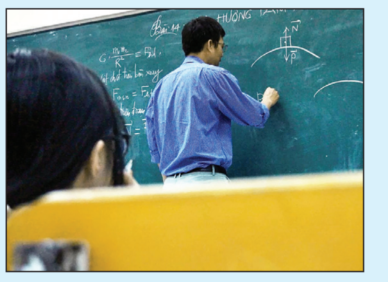

करना है। यूनेस्को अपने कार्यक्रमों के द्वारा विश्व को शिक्षा, विज्ञान, शांति एवं प्रगति का सन्देश देने के लिए कृत संकल्पित है। प्राचीन समय से भारत शिक्षा का बड़ा केन्द्र रहा है और उसने संसार में जगतगुरु की भूमिका निभाई है।

आर्थिक आपाधापी, आतंक, युद्ध एवं हिंसा के आधुनिक युग में शिक्षकों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वे छात्रों को न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि उन्हें जीवन में जरूरी कौशल भी सिखाते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ सहयोग करते हुए उन्हें नैतिक मूल्यों एवं शांतिपूर्ण जीवन के बारे में भी समझाते हैं जो एक अच्छे नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षक को ऐसे छात्र तैयार करने होंगे जो वैज्ञानिक-आध्यात्मिक हो, जिनमें बौद्धिकता एवं भावनात्मकता के साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास हो। प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉ. ए. एस. अल्तेकर ने लिखा है-''शिक्षा प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्त्रोत है, जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है।'' जब आधारभूमि मजबूत बन जाती है, नींव और खम्भे मजबूत बन जाते हैं तब प्रासाद को खड़ा किया जा सकता है। जब वैयक्तिक चेतना पवित्र बनती है जब सामुदायिक चेतना के विकास की बात आती है, यही विश्व चेतना को मजबूती देती है। विश्वमानव के आधार पर होने वाली शिक्षा तभी पवित्र एवं प्रभावी होगी, जब उसकी पृष्ठभूमि में मानवीय चेतना या वैयक्तिक चेतना की भूमिका पवित्र बनी हुई है।

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ''संसार में शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जो दुनिया को बदल सकती है।'' युद्ध के विचार मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के विचार ग्रहण करने की सबसे श्रेष्ठ अवस्था बचपन है। मानव मस्तिष्क में शान्ति के विचार बचपन से ही डालना होगा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को सारे विश्व से प्रेम करने के विश्वव्यापी दृष्टिकोण को विकसित करें।

पाकिस्तान में विलुप्ति के कगार पर लोकतंत्र

मरिआना बाबर

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान उसी समय से आंदोलनकारी और विध्वंसकारी राजनीति में शामिल हैं, जब कुछ साल पहले नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये उनकी सरकार को गिरा दिया गया था, और ऐसा पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ था। प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के ठीक पहले, घायल बाघ की तरह उन्होंने घोषणा की थी कि 'सरकार से बाहर रहने पर मैं पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा।'

ये शब्द सही साबित हुए, हालांकि वह अपनी बेगम बुशरा बीबी के साथ विभिन्न मामलों में जेल में कैद हैं। उन्होंने पिछले कई वर्षों में अपने समर्थकों को कानून तोड़ने और इस्लामाबाद के अति सुरक्षित इलाके में भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए भड़काया है, जहां संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन और विदेशी दूतावास स्थित हैं। भले ही विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अब तक किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने इस तरह से सरकार को शर्मिंदा नहीं किया है। विरोध प्रदर्शन ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों से दूर ही होते रहे हैं।

पाकिस्तान में हर जगह के लोग अब इस बात से तंग आ चुके हैं कि सरकार ने शहरों में प्रवेश और निकास मार्ग सील कर दिए हैं, जिससे न केवल व्यापारिक घरानों को, बल्कि आम नागरिकों को भी स्वतंत्र रूप से कहीं आने-जाने में परेशानी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि कभी-कभी कई दिनों तक पूरा शहर बंद रहता है। इस हफ्ते एक बार फिर, मलयेशियाई प्रधानमंत्री इस्लामाबाद आने वाले हैं। इसके अलावा, इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक भी होनी है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, इमरान खान ने एक बार फिर इस्लामाबाद के संवेदनशील क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन का आह्वान

किया है। अतीत में किसी भी हाई प्रोफाइल राजनीतिक कैदी को अपने समर्थकों, वकीलों, मित्रों और परिवार के साथ रोजाना मिलने की सुविधा नहीं थी। जबकि रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान को मीडिया से भी रोजाना बात करने की अनुमति है। इसके परिणामस्वरूप पत्रकारों को दिए गए बयानों और टिप्पणियों की खबरें पहले पन्ने पर छपती हैं।

इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अविश्वसनीय घटना घटी, जब पीटीआई के एक वकील ने मुल्क के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा के सामने अपना पक्ष रखते हुए धमकी दी कि यदि बड़ी बेंच ने पीटीआई द्वारा दायर मामले के खिलाफ फैसला सुनाया, तो अदालत के बाहर पीटीआई के 500 वकील इंतजार कर रहे हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधान न्यायाधीश ने तुरंत पुलिस बुला ली। उन्होंने पूछा, 'क्या आप चाहते हैं कि संस्थाएं धमकियों से चलें? मेरी एकमात्र गलती यह है कि मैंने हमेशा धैर्य दिखाया है।'

इस कॉलम में इमरान खान की विनाशकारी राजनीति की ओर ध्यान दिलाने की मुख्य वजह यह है कि आज पाकिस्तान की सभी संस्थाएं एक-दूसरे से टकरा रही हैं और इस नवजात लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो रहा है। सेना, उच्च न्यायपालिका, शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार, संसद और विपक्ष सभी एक-दूसरे से टकराव की स्थिति में हैं, ताकि यह साबित किया जा सके कि कौन अधिक शक्तिशाली है, जो उच्च न्यायपालिका को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधान न्यायाधीश और सेनाध्यक्ष, दोनों का कार्यकाल 2024 के अंत में पूरा हो जाएगा, बशर्ते सरकार उनके कार्यकाल को विस्तार न दे, जैसा कि अतीत में देखा गया है। पूर्व मंत्री और सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, 'राजनीतिक अभिजात वर्ग सिर्फ लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन वे उसमें विश्वास नहीं करते। पाकिस्तान में तानाशाही एक मानसिकता है। हमारा शासक वर्ग (चाहे सैन्य हो या निर्वाचित) लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। वे असहिष्णु हैं। राजनीतिक ताकतों के बीच सह-अस्तित्व की कोई वास्तविक इच्छा नहीं है।'

शीर्ष अदालत में भी खुलेआम मतभेद हैं, जहां अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश खुलेआम प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जब उन्हें किसी मामले की सुनवाई के लिए नामित किया जाता है, तो वे उससे इन्कार कर देते हैं। यह मुद्दा तब शुरू हुआ, जब सेना और शहबाज शरीफ सरकार ने मिलकर संसद में कुछ सांविधानिक संशोधन विधेयक लाने का प्रयास किया, जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता कम करने, प्रधान न्यायाधीश के कार्यकाल में बदलाव लाने, मौजूदा प्रधान न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद नए मुख्य न्यायाधीश का नाम तय करने और सांविधानिक न्यायालयों के निर्माण का प्रस्ताव शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि संविधान संशोधनों का पूरा मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है। सत्ता पक्ष के पास ऐसे सांविधानिक संशोधन करने के लिए न तो नेशनल असेंबली में और न ही सीनेट में दो तिहाई बहुमत है। इससे खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिला है।

इसी दौरान निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतने वाले पीटीआई के 80 उम्मीदवारों के बारे में एक और मामला उठा, क्योंकि पीटीआई के चुनाव चिह्न 'क्रिकेट बैट' को प्रधान न्यायाधीश द्वारा चुनाव चिह्नों की सूची से हटा दिया गया था। इस निर्णय की व्यापक निंदा की गई थी। चुनाव आयोग ने उन्हें संसद में?पीटीआई बेंच से जुड़ने की अनुमति नहीं दी है और वे पार्टी लाइन पर वोट नहीं कर सकते हैं। इसलिए पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और उन लोगों को पीटीआई की बेंच पर बैठने की अनुमति दी। लेकिन चुनाव आयोग और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने से इन्कार करते हुए कहा कि वे फैसले को स्वीकार या लागू नहीं करेंगे।

सरकार को डर है कि अगर विपक्ष का संख्याबल बढ़ गया, तो शहबाज शरीफ निचले सदन में अपना बहुमत खो सकते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्री नियाज मुर्तजा कहते हैं, 'पाकिस्तान का लोकतंत्र अब एक संकटग्रस्त प्रजाति बन गया है, जिसका लंबे समय से सैन्य तत्वों द्वारा शिकार किया जा रहा है। लेकिन लगता है कि अब इसे विलुप्त प्रजाति बनाने की तैयारी कर ली गई है, जिसके बाद इसे समुद्र में दफना दिया जाएगा, ताकि लोकतंत्र प्रेमियों को इसकी कब्र बनाने के लिए इसके अवशेष भी न मिल सकें।'

आज का इतिहास

1915 बुल्गारिया ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया।
1944 फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1948 तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्क़ाबात में भूकंप से 110,000 लोगों की मौत हुई।
1963 यू.एस. ने वाणिज्यिक आयात कार्यक्रम, दक्षिण वियतनाम के लिए अपने मुख्य आर्थिक समर्थन को निलंबित कर दिया, राष्ट्रपति न्गो दीन्ह दीम द्वारा बद्धवाद के उत्पीड़न के जवाब में।
1969 मोंटी पायथन फ्लाइंग सर्कस पहले बीबीसी वन पर प्रसारित हुआ।
1970 मॉन्ट्रियल में अक्टूबर संकट को भड़काते हुए फ्रंट डे लिबेरेशन डू क्यूबेक के सदस्यों ने ब्रिटिश राजनयिक जेम्स क्रॉस का अपहरण कर लिया।
1970 पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस को ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में अस्थि मत बनाओ लहर समिति में शामिल किया गया था।
1973 सात देशों ने यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, स्वायत्त कानूनी व्यवस्था प्रदान की जिसके अनुसार यूरोपीय पेटेंट स्वीकृत हैं।
1975 डर्टी वॉर-गुरिल्ला समूह मोंटोनियर्स ने ऑपरेशन प्रिमिसिया को अंजाम दिया, जिसमें एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें उन्होंने एक एयरोलीनस अर्जेंटिनास की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया, फॉर्मोसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया और एक सैन्य रेजिमेंट को ढेर कर दिया।
1986 ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स ने एक पूर्व परमाणु तकनीशियन मोर्दचाई वनुनु की कहानी प्रकाशित की, जिसमें इजरायल की परमाणु क्षमता का विवरण था।
1988 ब्राजील की संविधान सभा ने संविधान को मंजूरी दी।
2001 अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी बैरी बॉन्ड्स ने अपने मील के पत्थर के साथ 71 वें और 72 वें घरेलू रन के साथ मार्क मैकगवायर के सीजन-होम रन को पीछे छोड़ दिया।
2005 इंग्लैंड के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी वेन रूनी को आधिकारिक फीफा विश्व कप चैरिटी के प्रोत्साहन में इंग्लैंड के लिए फीफा एसओएस राजदूत के रूप में नामित किया गया है।
2006 जर्मन विशेषज्ञों ने देश के सौएरलैंड क्षेत्र में मेंडेन-बर्गे के एक सामूहिक कब्र से 51 कंकालों की खोज की है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी नरसंहारों के पीड़ितों के अवशेष थे।
2009 चीन ने उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को सुधारने का वादा किया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके।

राजनीति में बढ़ता परिवारवाद का दायरा

बलबीर पुंज

भारतीय राजनीति को परिवारवाद किस प्रकार अपनी जद में ले चुका है, तमिलनाडु का हालिया घटनाक्रम उसका उदाहरण है। यहां द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (द्रमुक) के मुखिया और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करते हुए अपने 46 वर्षीय पुत्र उदयनिधि स्टालिन को उप-मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। 29 सितंबर को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा उदयनिधि के साथ चार और मंत्रियों को पद-गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तमिलनाडु और द्रमुक में ऐसा पहली बार नहीं है, जब पिता मुख्यमंत्री और बेटा उप-मुख्यमंत्री रहे हो। वर्ष 2009 में एम.के. स्टालिन को भी उनके पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने उप-मुख्यमंत्री बना दिया था।

जहां स्टालिन की चुनावी राजनीति की शुरूआत वर्ष 1984 में हुई, तो वहीं स्टालिन के बेटे उदयनिधि पहली बार वर्ष 2021 में विधायक चुने गए। डेढ़ साल बाद ही उदयनिधि मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, तो अब वे राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं। ये वही उदयनिधि हैं, जिन्होंने गत वर्ष सनातन संस्कृति की डेंगू-मलेरिया-कोरोना आदि बीमारियों से तुलना करते हुए उसे समाप्त करने की बात कही थी। करुणानिधि परिवार की तीसरी पीढ़ी उदयनिधि का हालिया प्रमोशन ऐसे समय हुआ है, जब द्रमुक अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 1949 में सी.एन. अन्नादुरै ने पार्टी की स्थापना की थी। 1969 में उनकी मृत्यु के बाद पार्टी की कमान करुणानिधि के पास चली गई, जो तब प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने अपने परिवार को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने बेटे स्टालिन को उत्तराधिकारी बनाने की हठ ने वैको जैसे नेताओं को दरकिनार कर दिया, जो तब करुणानिधि के बाद पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त थे। इस कलह के कारण 1994 में द्रमुक का विभाजन हो गया।

पार्टी में स्टालिन को अगली चुनौती उनके ही बड़े भाई एम.के. अलागिरी से ही मिली, जिन्हें 2014 में पार्टी से निकाल दिया गया। करुणानिधि की बेटी कनिमोझी पार्टी की लोकसभा सांसद है। द्रमुक के भीतर स्टालिन के बाद उदयनिधि के उभार के खिलाफ बहुत कम चुनौती दिखती है। गांधी जी परिवारवाद के मुखर विरोधी थे। स्वतंत्रता के बाद उनके बड़े बेटे हरिलाल ने लावारिसों की भांति मुंबई स्थित अस्पताल में दम तोड़ा था। परंतु गांधीजी के नाम पर राजनीति करते हुए स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी इकलौती पुत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर देश में वंशवादी राजनीति का बीजारोपण कर दिया। उस कालखंड में अधिनायकवादी मानसिकता का परिचय देते हुए इंदिरा ने पं.नेहरू को जनता द्वारा चुनी केरल की तत्कालीन वाम सरकार को बर्खास्त करने और वहां राष्ट्रपति शासन थोपने के लिए विवश कर दिया था।

इस घटनाक्रम ने कांग्रेस में एक व्यक्ति और एक परिवार के साथ पूर्ण देश और पार्टी की पहचान को जोडने़ की गैर-लोकतांत्रिक परंपरा की नींव डाल दी।

व्यक्तिवाद से प्रेरित होकर इंदिरा ने न केवल देश पर आपातकाल (1975-77) थोप दिया, बल्कि अपने छोटे बेटे संजय गांधी को अपना उत्तराधिकारी भी बनाना शुरू कर दिया। तब संजय बिना किसी अधिकार के तत्कालीन इंदिरा सरकार के कामकाज में दखल देते थे। जून 1980 में हवाई दुर्घटना में संजय की मौत के बाद राजीव औपचारिक रूप से राजनीति में आए, जो कालांतर में अपनी मां की निर्मम हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद कुछ अपवाद को छोड़ दें, तो कांग्रेस पर प्रत्यक्ष-परोक्ष से नेहरू-गांधी परिवार (सोनिया-राहुल-प्रियंका) का प्रभुत्व है और पार्टी में योग्यता-प्रतिभा का स्तर इसी परिवार तक सीमित है।

पिछले सात दशकों में कांग्रेस ने जो वंशवाद प्रेरित राजनीतिक नजीर पेश की है, उसका नतीजा है कि देश में कई दल (छत्रप सहित) परिवारवाद से ग्रस्त हो चुके हैं, जो वर्तमान समय में सत्तापक्ष और विपक्ष—दोनों में मिल जाएंगे। समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी। बाद में उनके बेटे अखिलेश यादव अपने पिता की भांति उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। मुलायम परिवार के अन्य कई सदस्य विभिन्न पदों (सांसद सहित) पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति अलग नहीं है। इसकी शुरूआत लालू प्रसाद यादव ने की थी, जिसे अब उनके बेटे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं।

लालू की पत्नी राबड़ी देवी भी अपने पति की तरह बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वर्ष 1999 में खड़ा किया था, जो पारिवारिक कलह के कारण पिछले साल दो फाड़ हो गई। पवार की बेटी सुप्रिया सुले अपने पिता के दल में कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद हैं। पार्टी टूटने से पहले शिवसेना की कमान भी बाल ठाकरे के बाद बेटे उद्धव और पोते आदित्य के हाथों में थी। तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में बुआओं (ममता-माया) और भतीजों (अभिषेक-आकाश) का वर्चस्व है। कश्मीर की राजनीति में दशकों से दो परिवारों— अब्दुल्ला (शेख-फारुख-उमर) और मुफ्ती (सईद-महबूबा-इल्तिजा) का दबदबा है, जिसे धारा 370-35ए के संवैधानिक क्षरण के बाद कड़ी चुनौती मिल रही है।

वर्तमान सत्ताधारी राजग सरकार के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी भी परिवारवाद के आरोपों से घिरी है। इसकी स्थापना रामविलास पासवान ने की थी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके भाई पशुपति कुमार ने पार्टी को संभाला, तो अब उनके बेटे चिराग पासवान पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे हैं। इसी प्रकार तेलुगु देशम पार्टी को एन.टी. रामाराव ने स्थापित किया था, जिसकी अगुवाई उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, जिनके बेटे नारा लोकेश अपने पिता की अगुवाई वाली आंध्र सरकार में मंत्री हैं। कर्नाटक से पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा स्थापित जनता दल (सैकुलर) पर भी उनके ही परिवार का दबदबा है। यही स्थिति ओडिशा में बीजू जनता दल की भी है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व बादल परिवार के हाथों में है, जिसका बीते दिनों पार्टी के भीतर विरोध भी हुआ था।

वास्तव में, मौजूदा दौर में देश के दो ही राजनीतिक दल— भाजपा और वामपंथी दल ऐसे हैं, जो परिवारवाद के रोग से मुक्त दिखते हैं। इन दोनों, जो एक-दूसरे के वैचारिक तौर पर विरोधी हैं— वहां केंद्रीय स्तर पर किसी एक परिवार का नियंत्रण नहीं है। जब भारत 2047 तक विकसित होने का सपना देख रहा है, क्या तब इस दौरान भारतीय राजनीति के संकीर्ण परिवारवाद से मुक्त होने की उम्मीद की जा सकती है?

इस्राइल के साथ युद्धविराम के लिए तैयार हो गया था हसन नसरल्ला

नितिन गौतम

लेबनान के एक मंत्री ने दावा किया है कि मौत से पहले हिजबुल्ला का पूर्व प्रमुख हसन नसरल्ला इस्राइल के साथ युद्धविराम के लिए तैयार हो गया था। हालांकि जैसे ही वह युद्धविराम के लिए तैयार हुआ, इस्राइली हवाई हमले में उसकी मौत हो गई। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दल्ला बोउ हबीब ने अमेरिकी मीडिया के साथ बातचीत में यह दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और फ्रांस को भी इस युद्धविराम के फैसले के बारे में बता दिया गया था। हसन नसरल्ला बेरूत के दक्षिणी इलाके दानियेह में एक बंकर में मौजूद था, जब 27 सितंबर को हुए

इस्राइल के हवाई हमले में उसकी मौत हो गई। हिजबुल्ला ने भी बयान जारी कर नसरल्ला की मौत की पुष्टि की है। हालांकि नसरल्ला की मौत कैसे हुई, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। नसरल्ला के शव पर चोट या किसी घाव के निशान नहीं हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस्राइली हमले से हुए धमाके की वजह से सदमा लगने से नसरल्ला की मौत हुई है। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि %वह (हसन नसरल्ला) युद्धविराम के लिए मान गए थे। अब्दल्ला बोउ हबीब ने ये भी बताया कि लेबनान की सरकार ने हिजबुल्ला के साथ चर्चा के अमेरिका और फ्रांस को भी संभावित युद्धविराम की जानकारी दे दी थी। लेबनान की संसद के सभापति नबीह बेरी ने हिजबुल्ला से बातचीत की थी। हमें ये भी बताया गया कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों द्वारा जारी किए जाने वाले साझा बयान पर सहमत हो गए हैं। लेबनानी मंत्री के अनुसार, 25 सितंबर को अमेरिका, फ्रांस और अन्य सहयोगी देश 21 दिन के युद्धविराम का एलान करने वाले थे और इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यक्रम से इतर मुलाकात भी हुई थी। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्धविराम के प्रस्ताव को बाद में अस्वीकार कर दिया और हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमलों का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खोमैनी ने भी हमले से कुछ दिन पहले ही हसन नसरल्ला को लेबनान छोड़कर ईरान आने की सलाह दी थी। दरअसल लेबनान में हिजबुल्ला के सदस्यों के पेजर्स में हुए धमाकों के बाद ही खोमैनी ने नसरल्ला को लेबनान में रहने को लेकर चेताया था। ईरान ने नसरल्ला से कहा था कि हिजबुल्ला में इस्राइल के लोग हैं और वे नसरल्ला को मारना चाहते हैं। खोमैनी ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरुशान को हसन नसरल्ला को यही संदेश देने के लिए लेबनान भेजा था। हालांकि इस्राइली हमले में नसरल्ला के साथ ही ईरानी कमांडर की भी मौत हो गई थी।

अपनी महिला नेताओं से असहज होती भाजपा?

हरीश गुप्ता

बॉलीवुड अभिनेत्री और पहली बार लोकसभा सांसद बनीं कंगना रणावत भाजपा की पहली ऐसी महिला नेता नहीं हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को शर्मिंदा किया है। वह पहले भी कई मौकों पर ऐसा कर चुकी हैं क्योंकि वह बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हाल ही में दावा किया कि 2020 में किसानों का विरोध प्रदर्शन भारत में 'बांग्लादेश जैसी स्थिति' पैदा करने की तैयारी थी और विरोध स्थलों से हत्या और बलात्कार की कई खबरें आईं। हरियाणा भाजपा में इस पर काफी हंगामा हुआ जो पहले से ही बैकफुट पर है और उसने रणावत की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। मानो इतना ही काफी नहीं था, उन्हें अपना बयान वापस लेने का भी निर्देश दिया गया।

भाजपा में शामिल होने से पहले ही वह विपक्षी नेताओं और पार्टियों के खिलाफ खराब टिप्पणी करने के लिए सुर्खियों में रही थीं। इन्हीं खूबियों की वजह से भाजपा नेतृत्व ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वह जीत गईं। लेकिन अब भाजपा को यह बेहद शर्मनाक लग रहा है क्योंकि वह किसी न किसी मुद्दे पर अपनी बात कहती रहती हैं। लेकिन यह पहली बार है जब उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि कंगना पहली भाजपा महिला नेता नहीं हैं जिन्होंने भाजपा को शर्मिंदा किया है। दिवंगत सुषमा स्वराज को छोड़कर पार्टी में ऐसी महिला नेताओं की लंबी सूची है। तेजतर्रार हिंदू आइकन प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश से बड़े जोर-शोर से लोकसभा में लाया गया। अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान वह किसी न किसी विवाद में फंसती रहीं। भाजपा की उमा भारती और कुछ हद तक स्मृति ईरानी के साथ भी असहजता रही। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का पार्टी आलाकमान से टकराव अभी भी जारी है। महाराष्ट्र की पंकजा मुंडे को लेकर भी भाजपा असहज रही थी, हालांकि अब सब ठीक है।

जम्मू-कश्मीर में लगभग हिंसामुक्त चुनाव संपन्न होने के बाद मोदी सरकार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बेहद खुश है। अपने पूर्ववर्तियों की विफलता के बाद वे ही इस पद पर बने हुए हैं; चाहे वह सत्यपाल मलिक हों या जी ।सी। मुर्मु, जो किसी न किसी विवाद में फंसे रहे। इससे पहले, मोदी सरकार ने 2014 से अगस्त 2018 तक एन ।एन। वोहरा को राज्यपाल के रूप में बनाए रखा था। जिन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नियुक्त किया था। वोहरा

ने 10 साल से ज्यादा समय तक राज्य की सेवा की। लेकिन यह मनोज सिन्हा ही थे जिन्होंने मोदी की इच्छा के मुताबिक काम किया। मलिक को गोवा और फिर मेघालय भेजे जाने के बाद मोदी से उनकी अनबन हो गई थी, जबकि जी ।सी। मुर्मु को सीएजी के रूप में दिल्ली लाया गया था।

मनोज सिन्हा 2017 में मुख्यमंत्री पद की दौड़ से चूक गए थे और 2019 में लोकसभा चुनाव भी हार गए थे। मोदी ने उन्हें जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया, जहां उन्होंने एक कुशल प्रशासक और चतुर राजनेता के रूप में अपनी योग्यता साबित की। अगर घाटी में भाजपा अलग-अलग समूहों और निर्दलीयों की मदद से सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो सिन्हा का ग्राफ और ऊपर जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि राज्य में नई सरकार के स्थिर होने के बाद उन्हें पर्याप्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। सिन्हा की आरएसएस में मजबूत जड़ें हैं और वे मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। कई लोग कहते हैं कि वे भाजपा अध्यक्ष पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि यह एक लंबी दौड़ होगी।

ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अन्य मुख्यमंत्रियों की राह पर चलने का फैसला किया है, जिन्होंने एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले या यहां तक कि अदालत के आदेश के आधार पर भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था।

लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने रुख पर अड़े रहे और जेल में रहते हुए लगभग छह महीने तक पद पर बने रहे। यह देखते हुए कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एजेंसियों पर आरोपपत्र दाखिल किए बिना या मुकदमे में तेजी लाए बिना लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें जेल में रखने के लिए कड़ी फटकार लगाई, कांग्रेस ने भी उसी राह पर चलने का फैसला किया है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की है और न ही इस्तीफा दिया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भाजपा से सीख ली है, यहां तक कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धारमैया की याचिका को खारिज किए जाने के बाद भी, जिसमें उनकी पत्नी को भूमि के 'अवैध' आवंटन की जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी गई थी। हालांकि विपक्ष उनके इस्तीफे के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन कांग्रेस आरोपपत्र दाखिल होने तक सिद्धारमैया के साथ खड़ी नजर आ रही है।

विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) और इंडिया फाउंडेशन की जबरदस्त सफलता के बाद, लुटियंस दिल्ली में एक तीसरा ऐसा संगठन भी उभरकर सामने आ रहा है। वीआईएफ की स्थापना अजित डोभाल ने की थी, जो बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए। वीआईएफ से जुड़े सभी लोगों ने, 2009 में जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था। उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसके कई प्रमुख लोग मोदी सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिर राम माधव के नेतृत्व वाला इंडिया फाउंडेशन आया जो सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। राम माधव कभी मोदी के करीबी थे और बाद में उन्हें वापस आरएसएस में भेज दिया गया और अब वे मोदी के खास आदमी के तौर पर जम्मू-कश्मीर में फिर से सक्रिय हैं।

2024 आते-आते वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम (डब्ल्यूआईएफ) के नाम से एक नया फाउंडेशन सामने आया। इसके मुखिया आरएसएस के वरिष्ठ नेता राम लाल हैं जो कई वर्षों तक भाजपा के महासचिव (संगठन) रहे। उनकी जगह बीएल संतोष ने ले ली। डब्ल्यूआईएफ के पीछे राम लाल ही मुख्य व्यक्ति हैं। दुनिया भर से विचारक, बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता चुपचाप इसकी प्रमुख बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आए। राम लाल का आरएसएस और भाजपा में बहुत सम्मान है और वे कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हैं।

संतों के समर्थन से सत्ता की राजनीति

राज कुमार सिंह

धर्म एवं राजनीति के घालमेल को लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जाता। फिर भी कई संत और राजनीतिक सत्ता परस्पर निकटता के लिए लालायित दिखते हैं। धर्मगुरुओं से दलों और नेताओं की निकटता की चर्चा चुनाव के समय ज्यादा होती है। दरअसल उनके रिश्तों का आधार ही चुनावी गणित है। इस निकटता की प्रवृत्ति राष्ट्रव्यापी है। कुछ संत सत्ता-राजनीति के गलियारों में प्रवेश भी कर चुके हैं।

कभी संत कुंभनदास ने लिखा था- 'संतन को कहा सीकरी काम/ आवत जात पन्हैया टूटीं, बिसरि गयौ हरि-नाम।' यह कविता मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लिखी गयी मानी जाती है। आशय था कि संत को सीकरी (तब की राजधानी, जिसे अब फतेहपुर सीकरी कहा जाता है) से क्या काम। तब बादशाह का हुक्म ही व्यवस्था होती थी। फिर भी संत को सत्ता से निकटता की चाह नहीं थी। शायद सत्ता भी नजदीकियों की अपेक्षा नहीं रखती थी, लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी दोनों की बढ़ती निकटता सवाल खड़े करती है। धर्म एवं राजनीति के घालमेल को लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जाता। फिर भी कई संत और राजनीतिक सत्ता परस्पर निकटता के लिए लालायित दिखते हैं। धर्मगुरुओं से दलों और नेताओं की निकटता की चर्चा चुनाव के समय ज्यादा होती है। दरअसल उनके रिश्तों का आधार ही चुनावी गणित है। इस निकटता की प्रवृत्ति राष्ट्रव्यापी है। कुछ संत सत्ता-राजनीति के गलियारों में प्रवेश भी कर चुके हैं।

चुनावी राजनीति को यह रिश्ता सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में प्रभावित करता है। इन राज्यों में ज्यादा चर्चा डेरा सच्चा सौदा की रहती है। इसलिए भी कि दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में असर वाला यह डेरा अपने प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के चलते विवादास्पद रहा है। प्रवचन से लेकर फिल्मी परदे तक छाने के महत्वाकांक्षी राम रहीम को हत्या और बलात्कार के अपराध में 20 साल की सजा सुनायी जा चुकी है। सजा सुनाये जाने पर अनुयायियों की हिंसा में हरियाणा में 38 लोग मारे गये थे। ऐसे बाबा के विरुद्ध

जांच और अदालत से सजा की प्रक्रिया की मुश्किलों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। कुछ लोग चिर-परिचित वाक्य दोहरा सकते हैं कि देर है, अंधेर नहीं या फिर कानून के हाथ लंबे होते हैं, पर यह विश्वास भी बाबा के मामले में टूटता दिखता है। राम रहीम को पांच साल में दस बार, कुल 265 दिनों की परोल या फरलो मिल चुकी है। हरियाणा में चुनाव की घोषणा 16 अगस्त को हुई, पर उससे पहले ही बाबा को 12 अगस्त को 21 दिन की फरलो मिल गयी। अब जब पांच अक्तूबर को मतदान है, तो राम रहीम को 20 दिन की परोल मिल गयी है। सुनारिया जेल, जहां राम रहीम सजा भुगत रहे हैं, के जेलर सुनील सांगवान को भाजपा से टिकट मिलने से तो इस स्वयंभू संत और सत्ता के संबंधों पर सवाल एवं संदेह और भी गहरे हो गये हैं। सत्ता की ऐसी उदारता का दूसरा उदाहरण शायद ही मिले, पर चुनावी राजनीति में बाबा का सिक्का चलता है।

हरियाणा में 2014 और 2019 में भाजपा की जीत में डेरा सच्चा सौदा की भूमिका बतायी जाती है। लोकसभा की पांच और विधानसभा की 22 सीटों पर डेरा का असर माना जाता है। सो, तमाम दलों के नेता वहां हाजिरी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि डेरा का सिक्का हर बार चल जाता हो। इस साल लोकसभा चुनाव में राम रहीम की अनुपस्थिति में डेरा संभाल रही उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत से भाजपा के पांच नेता समर्थन मांगने गये। डेरा ने भाजपा को समर्थन का ऐलान किया, पर पिछली बार सभी दस सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार पांच पर अटक गयी। पंजाब में भी 2002 में डेरा ने कांग्रेस का समर्थन किया और कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार बन गयी, लेकिन 2007 के चुनाव में डेरा के समर्थन के बावजूद कांग्रेस हार गयी। पंजाब और हरियाणा में डेरों की कमी नहीं। कुछ का असर अन्य राज्यों में भी है। ऐसा ही एक डेरा है राधास्वामी ब्यास। इसके वेबसाइट के मुताबिक, 1891 में स्थापित इस डेरे के अनुयायी 90 देशों में हैं, पर ज्यादा संख्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी डेरा जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के समय भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल और आप के नेताओं ने हाजिरी लगायी थी। पिछले दिनों डेरा की आंतरिक हलचल से राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज हो गयीं। खबर आयी कि डेरा मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने 45 साल के जसदीप सिंह गिल को उत्तराधिकारी बनाया है। कुछ ही घंटों में दूसरी खबर आयी कि गिल नये प्रमुख नहीं होंगे, बल्कि ढिल्लों के साथ ही बैठेंगे।

पंजाब के निरंकारी, नामधारी, नूर महल और सच्चखंड बल्ला डेरों का भी हरियाणा में कुछ असर है, पर कई स्थानीय डेरे ज्यादा प्रभावशाली हैं। सतलोक आश्रम के संत रामपाल जेल में हैं, पर क्षेत्रीय चुनावी असर की आस कई दल और उम्मीदवार लगाये रहते हैं। रोहतक स्थित मस्तनाथ मठ का असर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ तक है। नाथ संप्रदाय के इस मठ के महंत बाबा बालकनाथ राजस्थान में भाजपा विधायक हैं। वे सांसद भी रह चुके हैं, पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी नजदीकियां भी किसी से छिपी नहीं हैं। गौकरण धाम, कपिल पुरी धाम, कालीदास महाराज, ईश्वर शाह, महंत सतीश दास समेत कई डेरा अलग-अलग क्षेत्रों में असर रखते हैं। दलों और नेताओं से निकटता से परहेज किसी संत को नहीं लगता। आप कह सकते हैं कि 'अब तो संतों को भी सीकरी से ही काम।'

अकाली दल के पुनरुद्धार के लिए नेतृत्व पीछे हटे

इकबाल सिंह चन्नी

बेशक भारत की आजादी का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली जीत का श्रेय महात्मा गांधी, शिरोमणि अकाली दल और भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में किए गए अपार बलिदानों को जाता है। देश की आजादी का रास्ता आसान करने का श्रेय भी अकाली दल को जाता है। अपने अस्तित्व के 104 वर्षों के इतिहास के दौरान शिरोमणि अकाली दल पंथ और देश के लिए किए गए बलिदानों के कारण पंजाबियों के एक बड़े हिस्से के दिलों पर राज करता रहा है। पिछले कुछ सालों से अकाली दल नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसलों फिर चाहे वे धार्मिक हों, आर्थिक या सामाजिक हों, से पंजाब के लोग विशेषकर सिख समुदाय संतुष्ट नहीं था और इसी वजह से पिछले कई चुनावों में शिरोमणि अकाली दल को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और सत्ता से बाहर रहना पड़ा। सत्ता से बाहर होने के कारण अकाली दल के नेताओं में बेचैनी होने लगी और धीरे-धीरे अकाली नेतृत्व ने हाईकमान से बगावत करना शुरू कर दिया, इसलिए हाल के दिनों में अकाली दल न केवल टूट गया है बल्कि सिखों के मन से भी उतर गया है। 2 मुख्य अकाली गुटों, सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाला गुट और गुरप्रताप सिंह वडाला के नेतृत्व वाला अकाली दल सुधार आंदोलन का लगभग पूरा नेतृत्व किसी न किसी तरह से खुद को दोषी मानने लगा। इसके चलते सभी नेता श्री अकाल तख्त पर उपस्थित होकर अकाल तख्त के जत्थेदार को सफाई दे रहे हैं और श्री अकाल तख्त की सर्वोच्चता स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। सिख संगत अन्य राजनीतिक दलों की ऐसी गलतियों को माफ कर सकती है क्योंकि वे दल सिख अधिकारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और न ही खुद को सिखों की पार्टी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यदि कोई अन्य पार्टी सिखों के हितों के खिलाफ कुछ फैसले लेती है तो सिख संगत को वह फैसले उतने बुरे नहीं लगते जितने कि सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी अकाली दल के फैसले। यही एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस द्वारा सिखों के साथ की गई अनगिनत ज्यादतियों के बावजूद कांग्रेस कई बार सिखों का वोट पाने में सफल रही है। हालांकि कांग्रेस की तुलना में अकाली दल ने सिखों के साथ ऐसी कोई ज्यादती नहीं की है, लेकिन सिख समुदाय अकाली दल की कुछ गलतियों को माफ करने के मूड में नहीं दिख रहा, भले ही उसने अकाली दल को सजा दे दी हो पिछले कई चुनावों में हरा कर। इससे पता चलता है कि सिख समुदाय स्थापित नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर रहा है। इसी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था।जालंधर उप-चुनाव ने सिख नेतृत्व पर सिखों के अविश्वास की पक्की मोहर लगा दी। इसलिए यह दीवार पर लिखी इबारत की तरह स्पष्ट है कि सिख समुदाय पहले से आजमाए और परखे हुए सिख नेतृत्व पर दोबारा भरोसा नहीं करेगा। हालांकि, सिख संगत सिख हितों को सर्वोपरि रखते हुए पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को एक मजबूत पार्टी के रूप में देखना चाहती है, यहां तक कि अकाली दल के विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि पंजाब में अकाली दल का मजबूत होना राज्य के हित में है। लेकिन आज की स्थिति में यह संभव नहीं लगता। यदि अकाली दल नेतृत्व ईमानदारी से अकाली दल को पुनर्जीवित करना चाहता है, तो पूरे नेतृत्व को त्याग की भावना दिखानी होगी और खुद को पीछे हटाना होगा और अकाली दल की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपनी होगी, जिससे सिखों को कोई शिकायत नहीं हो। सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे खोजा जाए? आमतौर पर कहा जाता है कि उनके अलावा ऐसा कौन है जो अकाली दल को अच्छे से चला सके। सुखबीर सिंह बादल के समर्थक अक्सर कहते हैं कि बिना पैसे के पार्टी नहीं चल सकती, हालांकि यह बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है। सिख समुदाय नेताओं के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने से नहीं कतराता। हमारी आस्था का ताजा उदाहरण आम आदमी पार्टी है, जिसके पास न तो कोई संगठन था और न ही मजबूत आर्थिक आधार। लेकिन लोगों का उस पर विश्वास हो गया जिस कारण लोगों ने इस पार्टी पर वोट और नोट की बारिश कर दी। इसलिए, यदि अकाली दल की कमान ऐसे व्यक्ति के हाथों में दी जाए जो उपरोक्त बातों पर खरा उतरे और लोग उस पर विश्वास कर सकें तो निश्चित रूप से सिख संगत शक्ति, साहस और धन के साथ ऐसे नेता का समर्थन करेगी बशर्ते कि सिख संगत सबसे पहले किसी वयस्क व्यक्तित्व को नेता के रूप में स्वीकार करने की परंपरा से बाहर निकले।

लीवर कैंसर का उपचार

लीवर कैंसर, लीवर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। लीवर ऐसे तत्व उत्पन्न करता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। विषैले तत्वों, दवाओं और अल्कोहल आदि को हटाता है। पित्त निर्मित करता है, जिससे शरीर को वसा और कोलेस्ट्रॉल अवशोषण में सहायता मिलती है।

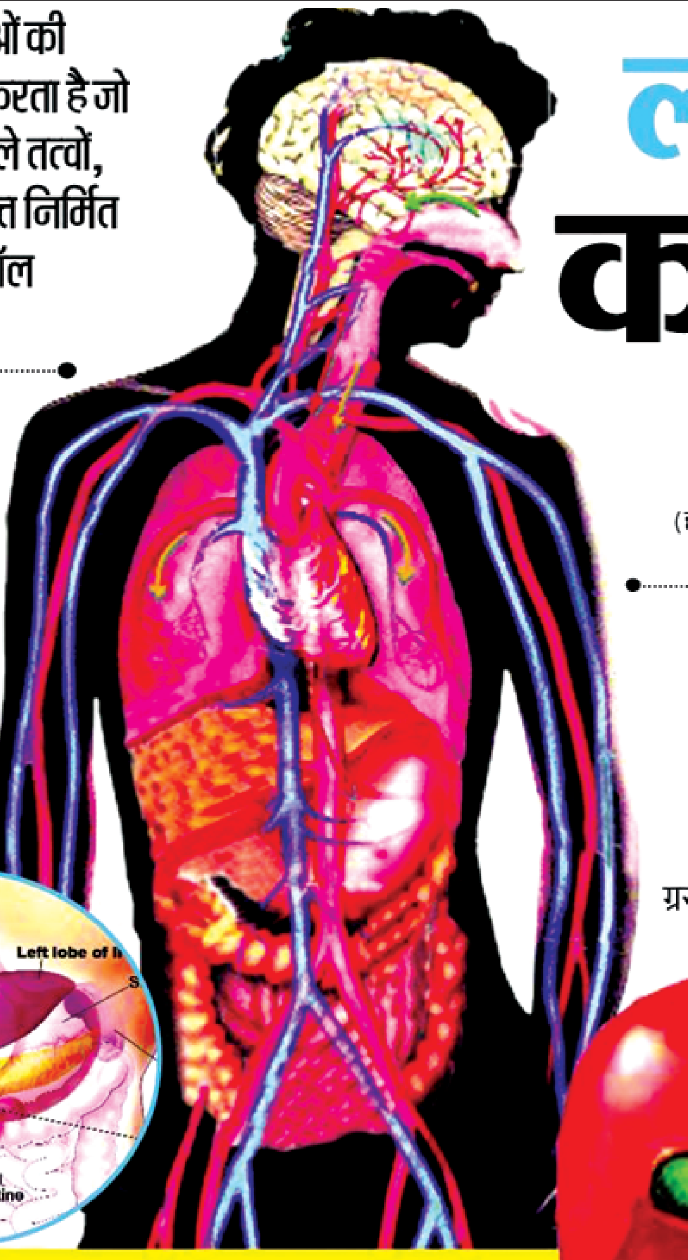

पुरुषों को बीमारी अधिक

यह संयुक्त राज्य और यूरोप में अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसायटी के अनुमान के अनुसार, हर वर्ष 17,000 से अधिक लोगों में प्राइमरी लीवर कैंसर का निदान पाया जाता है। इनमें से अधिकतर की उम्र 40 वर्ष से अधिक होती है और 15,000 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। संयुक्त राज्य में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में लीवर कैंसर के दोगुना मामले पाए जाते हैं।

कोशिकाएं फैलती हैं

संयुक्त राज्य में अधिकतर लीवर ट्यूमर, लीवर में अन्य अंगों मुख्य रूप से कोलोन, रेक्टिम, लंग, ब्रेस्ट, पैंक्रिया और स्टॅम से फैलते हैं। जब कोई कैंसर लीवर में अन्य कहीं से फैलता है तो कैंसर कोशिकाएं दोनों जगहों पर समान होती हैं। उदाहरण के लिए यदि फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर) लीवर तक फैलता है तो लीवर में पाई जाने वाली कैंसर युक्त कोशिकाएं फेफड़ों में पाई गई कैंसरयुक्त कोशिकाओं के समान ही होती हैं। इस कारण व्यक्ति का उपचार लीवर कैंसर के लिए नहीं, बल्कि लंग कैंसर के लिए किया जाता है। लीवर कैंसर को डॉक्टन मेटॉस्टेटिक लंग कैंसर कह सकते हैं।

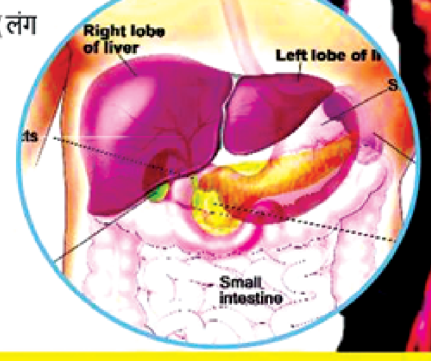

तीन प्रकार का लीवर कैंसर

प्राइमरी लीवर कैंसर के तीन मुख्य प्रकार हैं- हेपैटोसेलुलर कार्सिनोमा (हेपैटोमा या एचसीसी) हेपैटोसेलुलर कार्सिनोमा (हेपैटोमा या एचसीसी)। कोलनजियोकार्सिनोमा (बाइल डक्ट कैंसर)।

लीवर का कैंसर या तो लीवर में शुरू होता है या लीवर में शरीर के अन्य अंगों से फैलता है। प्राइमरी लीवर कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ठोस ट्यूमर है, जिसके एक मिलियन से अधिक मामलों का हर वर्ष निदान किया जाता है। इसमें 40 साल से अधिक उम्र के मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप डॉक्टर से उचित परामर्श लेकर इसका शीघ्र निदान करा सकते हैं।

जोखिम घटक

हेपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के ज्यादातर मामलों में हेपैटाइटिस बी और हेपैटाइटिस-सी जिम्मेदार होते हैं। हेपैटाइटिस-ए में लीवर कैंसर पनपने का खतरा नही बढ़ाता। सिरोसिस, जिसमें लीवर की कोशिकाओं पर अनेक कारणों से दाग बन जाते हैं। संयुक्त राज्य में सिरोसिस का सबसे प्रचलित कारण हेपैटाइटिस-सी और अधिक मात्रा में शराब पीना है। संयुक्त राज्य में 50 से 70 प्रतिशत लीवर कैंसर के मामले सिरोसिस से जुड़े होते हैं। कुछ अध्ययनों में इसका संबंध हेपैटोसेलुलर कार्सिनोमा से पाया गया है।

इनसे बढ़ता है खतरा

इस प्रकार का कैंसर पनपने का खतरा बढ़ा देती हैं जिनमें शामिल हैं- पित्ताशय की पथरी (गॉलस्टोपन्सक), पित्ताशय दाह (गॉलब्लडेर इन्फ्लेमेशन) और कई बार क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस (लार्ज बावेल में इन्फ्लेपमेशन होना)।

एंजियोसरकोमा (हेमन्जियोसरकोमा) - यह लीवर कैंसर का बहुत कम पाया जाने वाला प्रकार है।

हेपैटोब्लॉस्टोनमा - यह दुर्लभ प्रकार का कैंसर, आमतौर से 4 वर्ष की उम्र से छोटे बच्चों में पाया जाता है।

लीवर कैंसर के लक्षण

बीमारी बढ़ जाने तक इसके लक्षण आमतौर से नहीं दिखते। लक्षणों में ये शामिल किए जा सकते हैं-

- वजन में अप्रत्याशित कमी आ जाना।
- ठीक से भूख न लगना।
- थोड़ा खाना खाने पर भी पेट भरा हुआ लगना।
- पेट के ऊपर या दाएं हिस्से में दर्द या सूजन का होना।
- त्वचा और आंखों पर पीलापन होना।
- लीवर का फैल जाना या लीवर के क्षेत्र में किसी पिंड का बनना।
- क्रॉनिक हेपैटाइटिस या सिरोसिस की समस्या गंभीर हो जाना।
- रक्त में शर्करा (ब्लड शुगर) कम होना।
- पुरुषों में स्तन वृद्धि होना।

लीवर कैंसर का निदान

लीवर कैंसर का पता तब लगता है, जब बीमारी का स्तर बढ़ जाता है। प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण एकदम स्पष्ट नजर नहीं आते। डॉक्टर आपसे निम्न जांचें करा सकता है।

शारीरिक जांचें

वजन में कमी होने, कुपोषण, कमजोरी, लीवर का बढ़ना और इससे जुड़ी बीमारियां जैसे कि हेपैटाइटिस और सिरोसिस।

ब्लड टेस्ट

अल्फा-फेटोप्रोटीन नामक एक प्रोटीन के बढ़े हुए स्तर की जांच जिससे लीवर कैंसर का पता लग सकता है। कंप्यूटर का टेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन, एक प्रक्रिया ट्यूमर की खोज और लोकेशन जानने के लिए जिसमें एक्स-रे और कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग शरीर की अनुप्रस्थ (क्रॉस सेक्शूनल) छवियां निर्मित करने के लिए किया जाता है।

अल्ट्रा साउंड से जांचें

इसका उपयोग लीवर कैंसर की खोज और कैंसर युक्त (मैलिग्नेंथट) तथा कैंसर रहित (सामान्य) ट्यूमरों में अंतर के लिए किया जाता है।

डॉक्टर से कब संपर्क करें

यदि आपमें लीवर कैंसर का कोई भी लक्षण है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मुख्य लक्षण ये हैं- थकान, हल्का बुखार, त्वचा और आंखों का पीलापन (जांडिस), मांसपेशियों या जोड़ों का दर्द, मतली आना, मूत्र का गाढ़ा रंग, उल्टी होना, भूख न लगना और पेट में दर्द या सूजन आने पर आप डॉक्टर से परामर्श लेकर चिकित्सा करा सकते हैं।

लीवर कैंसर की चिकित्सा

उपचार कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कैंसर का स्तर, आपकी उम्र और आपका सामान्य स्वास्थ्य। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी प्रमुख उपचार विकल्प हैं। प्राय: इन तीनों को एक साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। सामान्यत: कोई अकेला ट्यूमर कैंसर जो लिम्फ नोड्स या दूसरे अंगों तक फैला नहीं हो, उसे सर्जरी से निकाला जा सकता है। हालांकि इस शुरुआती अवस्था में कम ही लीवर कैंसरों का पता लग पाता है। कुछ मामलों में, यकृत प्रत्यारोपण पर विचार किया जा सकता है। इसमें ट्यूमर्स की समस्या भी होती है। इसके अलावा कई तकलीफें साथ में बढ़ती जाती हैं।

बुढ़ापे की समस्याएं

उम्र बढ़ना एक एक प्राकृतिक और अपरिहार्य प्रक्रिया है, जिसे इंसान को हर हाल में स्वीकार करना होता है। उम्र बढ़ने के साथ ही आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन में बहुत से बदलाव आते है, जिसे स्वीकार कर उसके अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ता है।

शरीर में होने वाले बदलावों में विशेष तौर पर सेक्स क्षमता में कमी और मांस-पेशियों में बदलाव आता है। इसलिए आपको इसे स्वीकार कर इस परिवर्तन के साथ ही जीना पड़ेगा।

साध लेते हैं चुप्पी

अक्सर आदमी स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होने पर चुप्पी साध लेता है। भावनाओं को दबाने से उसके दिमाग में एक तरह का भावनात्मक हलचल होता है और इससे तनाव, निराशा और चिंता में वृद्धि होती है। अपने घरेलू व अन्य समस्याओं का हल ढूंढने और उस पर सलाह-मशविरा करने के लिए अपने खास लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहिए। अपनी भावनाओं को इस तरह दूसरे लोगों के साथ शेयर करने से व्यक्ति अपनी बढ़ती आयु से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से छुटकारा पा जाता है।

सकारात्मक सोचें

जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखें और जीवन के मध्य अवस्था का सामना करने के लिए मानसिक तौर पर पहले से ही तैयारी कर लें। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य में कई तरह का परिवर्तन होता है और इससे व्यक्ति के सेक्सुअल प्रदर्शन पर भी असर दिखने लगता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने आप को असक्षम और अयोग्य समझने लगता है और एक तरह से हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति में आत्मसम्मान में कमी, तनाव और निराशा जैसी बहुत सी बीमारियां मनौवैज्ञनिक समस्याओं के कारण पैदा होती हैं, जो आदमी के सेक्सुअल स्वास्थ्य को प्रभावित करने के साथ ही, उसके संपूर्ण स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं।

शेयर करें समस्याएं

व्यक्ति को चाहिए की अपनी पत्नी के साथ अपनी समस्याओं को शेयर करे। संभव है कि वह उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए कोई उपाय बताए और इससे तनाव और निराशा की स्थिति से निकलने में मदद मिले।

भरपूर लें आहार

हमेशा पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें और नियमित रूप से भोजन करें। प्रोसेस्ड और फैटी भोजन करने से परेहज करें और इसके बदले में प्रचुर मात्रा में ताजे फल और फाइबर युक्त आहार का सेवन करें।

एक्सरसाइज जरूरी

हर आयु में नियमित रूप से एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं कर हल्का-फुल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे शरीर के साथ दिमाग पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

ये भी रखें ध्यान

अपने वजन को हमेशा नियंत्रण में रखें। मोटापा एक साथ कई बीमारियों को निमंत्रण देता है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी और कुपोषण से बचने के लिए मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट लें। शरीर में किसी भी तरह का असहजता महसूस होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जीवन में काम-काजी बने, कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करते रहें।

युवाओं के दिल पर अटैक!

जवानी में तमाम लोगों के दिलों पर अटैक होता है, लेकिन आजकल के युवा हार्ट अटैक के भी शिकार हो रहे हैं। एक नई स्टडी में पता लगा है कि कम उम्र में इसके सबसे ज्यादा शिकार भारतीय युवा ही हैं।

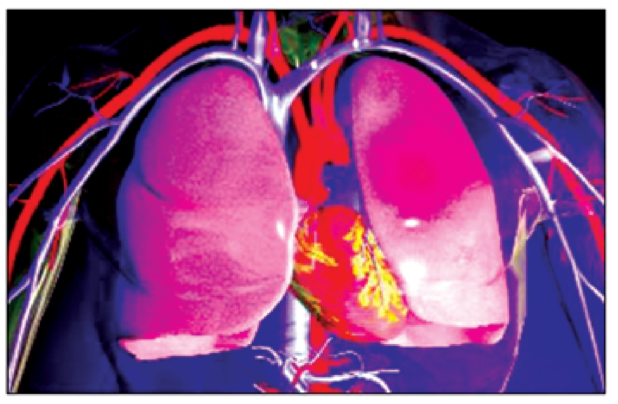

एक नए शोध से पता चलता है कि डिवेलप्ड कंट्रीज में जिस उम्र में हार्ट अटैक होता है, हमारे देश के लोग उसके 10 से 15 साल पहले इसके शिकार हो जाते हैं। गौरतलब है कि डिवेलप्ड कंट्रीज में 70 पर्सेंट हार्ट अटैक जहां 70 की उम्र के बाद होते हैं, वहीं हमारे देश में दो-तिहाई हार्ट अटैक 60 से कम उम्र वालों को होते हैं। हाल ही में आई एक स्टडी के मुताबिक, अब 30-40 की एज ग्रुप वालों का दिल भी सेफ नहीं है। मेडिकल साइंस की भाषा में यह एक्सट्रीमली प्रिमैच्योर स्टेज है।

दिल चाहता है नींद

हार्ट प्रॉब्लम की एक बड़ी वजह यंग इंडिया में नींद में कमी भी है। यंग प्रोफेशनल्स अक्सर अपनी नींद पूरी नहीं करते। अगर वे सोते भी हैं, तो उनका दिमाग अगले दिन के लिए चलता रहता है। दिनभर जो कुछ हुआ, वे उसे सोचते हैं और फिर दिमाग में अगले दिन की प्लानिंग चलती रहती है। इन सबके बीच कंफर्टेबल नींद का तो खात्मा ही हो जाता है। अच्छी नींद जरूरी है, आधी-अधूरी नहीं। जैसे कि रात को भी फोन बज रहा है, एसएमएस पढ़ रहे हैं। नींद की कमी से स्टैमिना खत्म होने लगता है और धड़कन तेज होने लगती है। बिजी लाइफस्टाइल की वजह से यूथ एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है।

खासकर कॉल सेंटर जैसी नाइट शिफ्ट जॉब करने वालों की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। वैसे तो उनके पास सोने के लिए दिन होता है, लेकिन तब वे दूसरे कामों में लगे रहते हैं और बस 2-4 घंटे की ही नींद लेते हैं। बकौल डॉ. चानना, हार्ट के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है। यही वजह है कि आजकल 25, 28 और 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। नींद के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है। लेकिन जब तक मेंटली फ्री नहीं होंगे, तब तक अच्छी नींद कैसे आएगी? रिसर्च बताती है कि 6 घंटे से कम सोने वालों को हार्ट अटैक होने की आशंका ज्यादा रहती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नींद पूरी लेनी चाहिए।

मस्ती से आठ घंटे सोएं

एक्सपर्ट्स का मानना है कि 6 घंटे की नींद बेहद जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे का काम फ्रेश होकर करें, तो 8 घंटे मस्ती से सोएं। लेकिन इसमें मेडिकेशन का स्कोप कम है और लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट का रोल ज्यादा है। आपकी डाइट और मेंटल बैलेंस सब मिलकर ही अच्छी नींद देंगे। अगर आप रात को 11 बजे ओवरइटिंग करते हैं, तो आपको अच्छी नींद कहां से आएगी। गौरतलब है कि जो लोग ज्यादा सोते हैं, उनका दिल भी अच्छी हालत में नहीं रहता। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादा देर तक सोना अक्सर

फ्रेगमेंटेड स्लीप होता है। नींद पूरी न होने के कारण ही लोग देर तक सोते रहते हैं। इसलिए स्लीप क्वालिटी मेंटेन करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा स्नोरिंग पर भी नजर रखने की जरूरत है। जो लोग ज्यादा खर्राटे लेते हैं, उन्हें अपनी स्लीप स्टडी करानी चाहिए।

सिमटे रहने से दिल सेफ नहीं

एक ओपन हार्ट सर्जरी इंस्टीट्यूट के बाहर लिखा था, दिल खोल लेते अपना अगर यारों के साथ, तो आज न खोलना पड़ता औजारों के साथ ...। जी हां, अपने आप में सिमटे रहने से भी दिल सेफ नहीं रहता। क्योंकि इससे स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाता। इन दिनों 28 से लेकर 40 तक उम्र वाले हार्ट पेशंट ज्यादा हैं। इसका मेन रीजन यह माना जाता है कि हमारा जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है। लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि अगर जेनेटिक रीजन है, तो पहले यह प्रॉब्लम क्यों नहीं थी ? दरअसल, पहले, दूसरे फैक्टर्स कंट्रोल में थे। डाइट और स्ट्रेस में ऐसा असंतुलन नहीं था। अब वेजिटेबल इनटेक कम हो गया है। सिर्फ मेट्रोज में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही है। ऐसे में यंगस्टर्स के लिए जरूरी है कि वे स्मोकिंग पर चेक रखें। रेग्युलर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। हर हाल में मेंटल स्ट्रेस कम करें। ग्रुप्स में मिलना और आपस में चीजों को शेयर करना जरूरी है। वर्कप्लेस में भी ग्रुप में घुले-मिलें।

हार्ट अटैक की दो अवस्थाएं

यंग हार्ट अटैक की दो कैटेगिरीज हैं। एक वह जिनके पैरेंट्स को भी यंग एज में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई थी। दूसरे वे जो अपनी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के चलते इसकी चपेट में आए। वजह चाहे जो भी हो, यूथ को अपने हार्ट की हेल्थ के लिए पहले से ही एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर हेरेडिटरी प्रॉब्लम है, तो 40 की उम्र होते ही रेग्यूलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल का चेकअप बेहद जरूरी है। इन सबके अलावा यूथ में हार्ट अटैक के लिए स्मोकिंग भी जिम्मेदार है। रॉन्ग इटिंग हैबिट्स भी दिल को बीमार कर सकता है।

जंक फूड में ट्रांस फैटी एसिड

जंक फूड में ट्रांस फैटी एसिड होते हैं, जो हार्ट के लिए नुकसानदायक होते हैं। पिज्जा और बर्गर जैसे फूड की बजाय फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स और कलरफुल फ्रूट्स खाना बेहतर रहेगा। दिनभर में कम से कम 5 बार कलरफुल फ्रूट्स और सलाद लें। दरअसल, इनमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। इसके अलावा ऑल्मंड और वॉलनट जैसे हेल्दी नट्स की 40-50 ग्राम क्वांटिटी हर रोज लेना चाहिए। दूसरे हर समय मोबाइल और कंप्यूटर से जुड़े रहने की वजह से यूथ की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। ऐसे में हफ्ते में पांच दिन 3-4 मील पैदल चलना फायदेमंद रहेगा। हर रोज 30-40 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग या वर्कआउट भी रुटीन में शामिल होना चाहिए।

रिस्क फैक्टर

- ओबेसिटी
- स्लीप डिस्ऑर्डर
- डायबिटीज
- एक्सरसाइज में कमी
- हाई कोलेस्ट्रॉल
- स्मोकिंग
- स्ट्रेस

यह भी करें

- हार्ट एक मसल है, इसलिए प्रोटीन रिच डाइट लें।
- स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज भी जरूरी है।
- हार्ट-स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लें।
- ग्रुप्स में घुले-मिलें। इससे स्ट्रेस कम होता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सीट बंटवारे पर तत्काल निर्णय लेने की जरूरत : शरद पवार

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-एससीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए महा विकास अघाड़ के भीतर सीट-बंटवारे की चर्चा पर तत्काल निर्णय लेने का आह्वान किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। 26 नवंबर से पहले राज्य में चुनावी प्रक्रिया खत्म होने की उम्मीद है। हालांकि, पवार ने यह भी कहा कि वह विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के भीतर हो रही सीट-बंटवारे की चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं। पवार ने कहा कि सीट-बंटवारे के मामले पर टिप्पणी करना उनके लिए उचित नहीं होगा। पवार ने कहा कि मैं अपनी पार्टी की ओर से सभी से एक साथ बैठकर चर्चा करने का अनुरोध करता हूं। निर्णय यथाशीघ्र हम तक पहुंचना चाहिए। लोग महाराष्ट्र में बदलाव चाहते हैं और यह स्थिति हमारे लिए अनुकूल है और हमें लोगों के मन की इस भावना का सम्मान करना चाहिए। पवार ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान एमवीए के भीतर कोई टकराव नहीं था।

कांग्रेस के 1800 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए ठोंका दावा

मुंबई। महाराष्ट्र में कांग्रेस इकाई को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए 1,830 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकांश आवेदक राज्य के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों से आए हैं। महाराष्ट्र में अभी मतदान की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हालाँकि, पार्टी के 288 में से लगभग 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। जबकि हरियाणा 5 अक्टूबर को मतदान के लिए पूरी तरह तैयार है, कांग्रेस पार्टी को केवल 90 सीटों के लिए 2,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में आवेदकों को 20,000 रुपये तक का पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है। सबसे पुरानी पार्टी के अनुसार, महाराष्ट्र को हरियाणा से अधिक आवेदक मिल सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रतिक्रिया लोकसभा चुनावों में पार्टी की हालिया सफलता के कारण है। कांग्रेस 13 लोकसभा सांसदों और एक निर्दलीय सांसद के साथ एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी है।

अरविंद केजरीवाल के खाली किया मुख्यमंत्री आवास

नईदिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने लुटियंस जोन में अपने नए पते पर जाने के लिए शुक्रवार को 6, फ्लैगस्टाफ रोड आवास खाली कर दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अपनी पत्नी और बेटे के साथ कार में घर से निकलते देखा गया। उनके माता-पिता और बेटी दूसरे में चले गए। इसके लिए सुबह से ही आवास में मिनी ट्रकों का प्रवेश शुरू हो गया। केजरीवाल, जिन्होंने पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, अपने परिवार के साथ मंडी हाउस के पास फिरोजशाह रोड पर पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के आधिकारिक आवास पर रहेंगे, जो रविशंकर शुक्ला लेन में आप मुख्यालय के करीब है। गुरुवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया भी राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो गए। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह घर आप के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह का आधिकारिक आवास है।

केजरीवाल के घर खाली करने पर स्वाती मालीवाल ने कसा तंज

नईदिल्ली। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पोस्ट एक्स के जरिए नेतृत्व और नैतिक मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। आधुनिक नेताओं की तुलना भगवान राम से करते हुए मालीवाल ने उनके त्याग और महिलाओं का सम्मान करने के तरीके में अंतर पर जोर दिया। मालीवाल ने एक्स पर लिखा। एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने महल छोड़ वन में 14 साल गुज़ारे। नारी सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि आज कल जो लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महा त्याग बताकर एक महल छोड़ दूसरे महल में रहने जाते हैं। माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं। नारी पर वार करने वाले को बचाते हैं, इसी में सुकून पाते हैं। मालीवाल ने भगवान राम के बारे में बात की, जिन्होंने अपना महल छोड़ दिया और रावण जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भी महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ते हुए 14 साल वनवास में बिताए और इसकी तुलना वर्तमान नेताओं से की।

सनातन धर्म की रक्षा के लिए बने संरक्षण बोर्डः पवन कल्याण

अमरावती। तिरुपति प्रसादम विवाद के आलोक में, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सनातन धर्म की रक्षा करने और इसके सिद्धांतों को कमजोर करने वाले कार्यों को रोकने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय कानून की स्थापना की वकालत की है। तिरूपति में वाराही घोषणा कार्यक्रम में बोलते हुए, कल्याण ने सनातन धर्म की रक्षा और पूरे भारत में एक समान प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अधिनियम की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड के निर्माण का प्रस्ताव रखा। कल्याण ने बोर्ड और उसकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वार्षिक धन के आवंटन का भी आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मंदिर के प्रसाद और प्रसाद में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सनातन धर्म प्रमाणन शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है कांग्रेस : शाह

नई दिल्ली। दिल्ली से जब्त ड्रग्स को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां मोदी सरकार नशामुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की रू. 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है।

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि ड्रग कारोबार से जुड़े 5,600 करोड़ रुपये की जब्ती के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी को भारतीय युवा कांग्रेस की दिल्ली इकाई के सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले पुलिस ने भी बताया था कि मुख्य आरोपी के एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेताओं के साथ कथित संबंध होने का पता चला है। भारत और विदेश के करीब एक दर्जन लोग पश्चिम एशिया के देशों से भारत में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी के अंतरराष्ट्रीय गिरोह में कथित रूप से संलिप्त थे।

इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ, वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार, ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना, ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशामुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है।

पुलिस ने बुधवार को दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर में एक गोदाम से 560 किलोग्राम से अधिक कोकीन और 40 किलोग्राम 'हाइड्रोपोनिक मारिजुआना' जब्त किया था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 5,620 करोड़ रुपये आंकी गई थी। मामले में विशेष शाखा ने चार लोगों दिल्ली निवासी तुषार गोयल (40), हिमांशु कुमार (27) और औरंगजेब सिद्दीकी (23) तथा मुंबई निवासी भरत कुमार जैन (48) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गोदाम में बोरियों में रखे गए 602 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ भी जब्त किए थे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि भारत में संचालित गिरोह के पीछे गोयल का दिमाग है। पूछताछ में पता चला कि चारों आरोपी दिल्ली और अन्य महानगरों में कंसर्ट, रेव पार्टी आदि में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बेचने की साजिश रच रहे थे। जांच के दौरान एक सोशल मीडिया खाते से गोयल की कई फोटो मिली हैं, जिसमें वह कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। गोयल के कथित फेसबुक खाते में उसकी प्रोफाइल पिक्चर में एक बाघ की तस्वीर है और उसने अपना परिचय भारतीय युवा कांग्रेस, डीवाईपीसी के दिल्ली प्रदेश आरटीआई प्रकोष्ठ का अध्यक्ष लिखा है। हालांकि, युवा कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि उसे पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 17 अक्तूबर, 2022 को संगठन से निष्कासित कर दिया गया था।

वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार कांग्रेस के पर्याय : नड्डा

भाजपा अध्यक्ष बोले- राहुल गांधी ने विदेश मे किया भारत का अपमान

शिमला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को अपने गृहराज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं कि लोकसभा के चुनाव में आपने हिमाचल की चारों सीट भाजपा को जिताई। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं हिमाचल की जनता को और हर वोटर को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि 60 साल बाद हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुए हैं।

नड्डा ने कहा कि मुझे इस बात की भी खुशी है कि ओडिशा में आप सबकी शुभकामनाओं से पहली बार विशुद्ध भाजपा की सरकार बनी है। आंध्र में एनडीए की सरकार बनी है। कुल मिलाकर देश के 18 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है, जिसमें से 13 प्रदेशों में भाजपा की विशुद्ध सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आप लोगों की अथक मेहनत और ताकत से आज 98त्न भू-भाग पर कमल खिला हुआ है। इसके लिए मैं भारत और हिमाचल की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

लोगों से नड्डा ने कहा कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित हुआ है, जब भाजपा शासन में आई और भाजपा को आपकी सेवा करने का मौका मिला। हिमाचल में भी अगर विकास का कोई पत्थर लगा है, तो उसके ऊपर भी भाजपा का निशान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जब भी आती है और जहां भी आती है, वहां जातिवाद, अलगाववाद और राष्ट्र विरोधी तत्व विराजमान होते हैं। जाति को जाति से लड़ाओ, मजहब को मजहब से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, वोटबैंक, तुष्टिकरण, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार, ये सब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं।

नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार कांग्रेस के पर्याय हैं। कांग्रेस पाकिस्तान के साथ बातचीत और नियंत्रण रेखा के पार व्यापार की वकालत करती है। क्या यह दृष्टिकोण बुद्धिमानीपूर्ण है? उन्होंने दावा किया कि हमनें गांव, गरीब, वंचित और पीड़ित के लिए काम किया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में हर गांव का विकास हुआ है, गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है, गांव-गांव में सीएससी कार्य कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया। वह बुरा बोलते है और नकारात्मकता और विभाजन फैलाते है। उनका कहना है कि एक समय आएगा जब हम आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन मैं दृढ़ता से कहता हूं, जब तक मोदी जी और भाजपा सत्ता में हैं, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा! उन्होंने आगे कहा कि यहां के मुख्यमंत्री सुक्खू जी कहते हैं कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा। सुक्खू जी, अगर केंद्र मदद न करे तो एक दिन भी हिमाचल की सरकार नहीं चल सकती। हर महीने केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपये रेवेन्यू डेफिसिट फंड में भेजती है, तब यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है।

महाराष्ट्र में चुनाव से पहले भाजपा को झटका

मुंबई। महाराष्ट्र भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अपने समर्थकों के साथ एनसीपी (सपा) में शामिल होंगे। इससे एक दिन पहले उन्होंने मुंबई में पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। मुलाकात गुरुवार को पवार से दक्षिण मुंबई में उनके सिल्वर ओक्स आवास पर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि शरद पवार ने उनसे उनकी पार्टी में शामिल होने और विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले महीने होने की संभावना है। इंदापुर सीट से चार बार विधायक चुने जा चुके हर्षवर्धन पाटिल फिर से इंदापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं।

भाजपा के साथ बैक चैनल बात कर रहे फारूक अब्दुल्ला?

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में चुनाव खत्म हो चुके हैं। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे भी आएंगे। सरकार बनाने के दावे सभी की ओर से किए जा रहे हैं। इन सबके बीच दावा किया जा रहा कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) की अहम भूमिरा रहने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर कई तरह की खबरें भी चल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन के लिए इंडिया ब्लॉक के बाहर के दलों के साथ किसी भी बैक चैनल बातचीत से इनकार किया, जिसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) भी एक हिस्सा है। हालाँकि, एनसी और पीडीपी दोनों ने चुनावों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में कोई चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं बनाया, जो एक दशक के बाद 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में हुए थे। नतीजे 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ घोषित किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा था, डॉ. फारूक अब्दुल्ला पहलगाम में किस बीजेपी प्रतिनिधि से एक बार नहीं बल्कि दो बार मिले थे? पहलगाम में क्या बातचीत हो रही है? भाजपा के निषिद्ध और वर्जित होने की तमाम बयानबाजी का क्या हुआ? चीज़ें जितनी अधिक बदलती हैं, उतनी ही अधिक वे वैसी ही रहती हैं। जब एक यूजर ने सवाल किया कि क्या यह अफवाह है या इसमें कुछ सच्चाई है, तो मट्टू ने जवाब देते हुए कहा, अफवाहें? पहलगाम में एनसी-बीजेपी की बातचीत स्वयं डॉ. फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई - जिसमें अराजनीतिक मध्यस्थ भी शामिल थे। एनसी इससे इनकार करे, मुझे दोनों बैठकों के नाम, विवरण, स्थान और समय साझा करने में खुशी होगी।%% किसी का नाम लिए बिना, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने परोक्ष संदर्भ में एक्स पर लिखा, और अब अपने आकाओं से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लोग किस प्रकार की ठगी से गुज़रे हैं। हालाँकि, फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी ने कहा कि जो लोग अपनी आसन्न हार को महसूस कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह के निराधार आरोप फैलाने का सहारा लिया है।

खेल
प्रमुख समाचार

हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी से नाखुश हैं कोच मोर्कल

ग्वालियर। भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत छह अक्तूबर से हो रही है। पहला मैच ग्वालियर में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर टीम इंडिया जमकर मेहनत कर रही है। बीसीसीआई ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में भारत की पेस बैटरी प्रैक्टिस सेशन के दौरान नेट्स में अपनी पूरी क्षमता से गेंदबाजी करती दिख रही है। वहीं, नए बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल गेंदबाजों से बात करते दिख रहे हैं। मोर्कल के सामने बांग्लादेश सीरीज से पहले काफी चुनौतियां हैं।

प्रैक्टिस सेशन में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी गेंदबाजी का अभ्यास किया। हालांकि, मोर्कल हार्दिक के गेंदबाजी के प्रति रवैये से नाखुश दिखे और दोनों ने इसमें सुधार को लेकर लंबी चर्चा की। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक स्टंप्स के काफी करीब से गेंदबाजी कर रहे थे और मोर्कल इससे खुश नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्वालियर में नेट्स सेशन के दौरान मोर्कल पांड्या के रन-अप पर काम कर रहे थे।

इस दौरान मोर्कल पांड्या की स्टंप के काफी करीब से गेंदबाजी करने से नाखुश लग रहे थे और उन्होंने पांड्या को इस बारे में जानकारी भी दी। ज्यादा नहीं बोलने के लिए मशहूर मोर्कल को हार्दिक को उनकी बॉलिंग मार्क पर लौटते वक्त हर बार कान में कुछ बोलते हुए देखा गया। मोर्कल ने कथित तौर पर हार्दिक की रिलीज प्वाइंट पर भी काम किया है। हार्दिक की बॉलिंग को देखने के बाद मोर्कल ने अपना ध्यान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और युवा हर्षित राणा और मयंक यादव पर केंद्रित कर दिया। मयंक का पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ है। इस पेसर के पास लगातार 150+ की स्पीड से गेंद फेंकने की क्षमता है। वहीं, हर्षित पिछले कुछ समय से भारतीय टी20 टीम का हिस्सा हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 808 अंक गिरा निफ्टी 25,000 के करीब

नईदिल्ली। शेयर बाजार में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन यानी 4 अक्टूबर को लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। आज मार्केट की शुरुआत तो शानदार उछाल के साथ हुई लेकिन यह बढ़त बनाए रखने में कामयाब नहीं हो सका। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स 808.65 अंक या 0.98% गिरकर 81,688.45 के लेवल पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी-50 25,000 के लेवल के करीब पहुंच गया। इसने 200.25 अंक या 0.79% की गिरावट दर्ज की और 25,049.85 के लेवल पर क्लोज हुआ। एनालिस्ट्स का मानना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष से उपजी चिंताओं के मद्देनजर टॉप तेल उत्पादक देशों से कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट आने की आशंका है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतों में उछाल आएगा और उसका असर भारत जैसे आयातक देशों पर देखने को मिलेगा। भारत पूरी तरह से कच्चे तेल के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है।

सितंबर में प्याज-आलू की कीमतों ने बिगाड़ा बजट

नईदिल्ली। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल से सितंबर में घर का बना खाना एक साल पहले की तुलना में महंगा हो गया। शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2023 में शाकाहारी भोजन की लागत 28.1 रुपये से सितंबर में 11 प्रतिशत बढ़कर 31.3 रुपये हो गई। यह अगस्त में 31.2 रुपये से थोड़ी ही अधिक हुई। 'रोटी, राइस, रेट' नामक इस रिपोर्ट में वृद्धि के लिए सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो थाली की लागत का 37 प्रतिशत हिस्सा है। इसमें कहा गया, '' सितंबर में प्याज, आलू तथा टमाटर की कीमतें क्रमशः 53 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 18 प्रतिशत बढ़ीं। इसकी वजह प्याज तथा आलू की कम आवक, जबकि भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में टमाटर का उत्पादन प्रभावित रहना रही।''

टेमासेक की नजर हल्दीराम स्नैक पर

नईदिल्ली। सिंगापुर की टेमासेक होल्डिंग भारत की स्नैक कंपनी हल्दीराम स्नैक प्रा.लि. में अल्पांश हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस डील से हल्दीराम की वैल्यू करीब 11 बिलियन डॉलर तक आंकी जा सकती है। सिंगापुर की राज्य निवेशक कंपनी हल्दीराम में 10 से 15 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए शुरुआती बातचीत कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यह बातचीत गोपनीय है, इसलिए पहचान नहीं बताई जा रही है। यह निवेश हल्दीराम के संभावित आईपीओ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत चल रही है और इसका कोई सौदा होना जरूरी नहीं है। हल्दीराम के नाम से मशहूर कंपनी में अन्य संभावित बोली लगाने वालों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। इस मामले में टेमासेक के प्रतिनिधि ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि हल्दीराम की ओर से भी तुरंत कोई जबाव नहीं मिला।

एप्पल भारत में खोलेगा 4 नए स्टोर

नईदिल्ली। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में चार और स्टोर खोने जा रही है। नए स्टोर पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में खोले जाएंगे। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा, कंपनी जल्द अपने पहले 'मेड इन इंडिया' आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स भी पेश करेगी। एप्पल के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट (रिटेल) डेयरड्रे ओब्रायन ने कहा, '' हम अपनी नयी टीमें बना कर खुश हैं। हम भारत में और अधिक स्टोर खोलने की योजना बना रहे हैं। हम इस देश में अपने ग्राहकों के जुनून से प्रेरित हैं। बता दें कि एप्पल ने अप्रैल 2023 में भारत में अपने पहले दो स्टोर दिल्ली और मुंबई में खोले थे। माना जा रहा है कि नए स्टोर अगले वर्ष खोले जा सकते हैं। बयान में कहा गया, '' एप्पल अब भारत में आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स समेत सभी आईफोन 16 मैन्युफेक्चर कर रहा है।''

चीन ने कैसे अपने निजी क्षेत्र का गला घोंट दिया

एलेनोर ओल्कोट और वांग जुएकियाओ

बीजिंग स्थित एक कार्यकारी ने उच्च जोखिम वाली स्टार्ट-अप कंपनियों में निजी निवेश के कारोबार का जिक्र करते हुए कहा, ''अमरीका के बाद चीन दुनिया में सबसे अच्छा वी.सी. गंतव्य हुआ करता था।'' संस्थापकों और निवेशकों को कोविड 19 महामारी से पहले के गौरवशाली वर्षों में वापसी की बहुत कम उम्मीद है, जब अलीबाबा और टेनसैंट जैसी कंपनियां तेजी से आर्थिक विकास और मोबाइल इंटरनैट के उदय का लाभ उठाकर वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी कंपनियां बन गई थीं। कार्यकारी ने आगे कहा, ''पूरा उद्योग हमारी आंखों के सामने ही खत्म हो गया है। उद्यमी भावना खत्म हो गई है। यह देखना बहुत दुखद है।'' आंकड़ों में भी निराशा का भाव झलकता है। डाटा प्रदाता आई.टी. जूजी के अनुसार, 2018 में, जब वी.सी. निवेश अपने चरम पर था, चीन में 51,302 स्टार्ट-अप स्थापित किए गए थे। 2023 तक, यह आंकड़ा गिरकर 1,202 पर आ गया और इस साल और भी कम होने की संभावना है।

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफैसर के.यू. जिन का कहना है कि उद्योग 'चीन की उद्यमशीलता की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने चेतावनी दी,''वैश्विक निवेश का बहिर्वाह और चीनी कंपनियों के मूल्यांकन में भारी गिरावट देश के नवाचार अभियान को प्रभावित करेगी।'' इस क्षेत्र में संकट आंशिक रूप से चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी को दर्शाता है, जो लंबे समय तक चले कोविड-19 लॉकडाऊन के कारण प्रॉपर्टी बबल के फटने और इसके इक्विटी बाजारों में ठहराव से प्रभावित हुई है। जैसे-जैसे द्विपक्षीय तनाव बढ़ा है, अमरीका स्थित निवेशक भी बड़े

पैमाने पर बाहर निकल गए हैं। लेकिन यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा लिए गए राजनीतिक निर्णयों का प्रत्यक्ष परिणाम भी है, जिसने चीन में निजी व्यवसाय के लिए माहौल को नाटकीय रूप से बदल दिया है जिसमें एकाधिकारवादी या कम्युनिस्ट पार्टी के मूल्यों के अनुरूप न होने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कार्रवाई और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शामिल है, जो व्यवसाय समुदाय में व्याप्त है।

अलीबाबा के जैक मा और टेनसैंट के पोनी मा जैसे संस्थापकों ने चीनी उद्यमियों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया, जो अपनी कंपनियों को सार्वजनिक करके एक बड़ा भाग्य बनाना चाहते थे। 2020 की अंतिम तिमाही तक, दोनों कंपनियों की कीमत संयुक्त रूप से 1.5 ट्रिलियन थी। नवंबर 2020 में यह सपना उस समय टूटना शुरू हो गया, जब बीजिंग ने अलीबाबा से अलग होकर बनी एक फिनटेक कंपनी एंट ग्रुप के आई.पी.ओ. को रद्द कर दिया। जैक मा को अधिकारियों ने 'पर्यवेक्षी साक्षात्कार' के लिए बुलाया, जिससे प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर व्यापक कार्रवाई शुरू हुई, जिसने चीन में निवेश की अप्रत्याशितता को रेखांकित किया। तब से, जोखिम लेने वाले उद्यमियों की एक पीढ़ी को प्रेरित करने वाला आशावाद व्यवस्थित रूप से खत्म हो गया है। शंघाई में एक सीरियल संस्थापक कहते हैं, ''कंपनी शुरू करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। हमें जोखिम क्यों उठाना चाहिए? हमने 5 साल तक स्टार्ट-अप खो दिए हैं।'' कई स्टार्ट-अप कंपनियों ने निवेशकों को इस आधार पर हिस्सेदारी बेची कि अगर वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हुए या किसी निश्चित तिथि तक अधिग्रहित नहीं हुए तो वे उन शेयरों को वापस खरीद लेंगे। लेकिन विफलताओं की एक लहर ने वी.सी. फर्मों को अदालतों के माध्यम से अपनी दिवालिया निवेशित कंपनियों से संपत्ति वापस लेने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया है। चीनी व्यापार प्रकाशन कैक्सिन ने अगस्त में बताया कि देश के प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाली वी.सी., शेन्जेन कैपिटल ग्रुप ने 2023 से 41 मुकद्दमे दायर किए हैं, जिनमें से 35 उन कंपनियों के खिलाफ थे जो एक निर्धारित तिथि तक सार्वजनिक होने में विफल रहीं और शेयरों को पुनर्खरीद नहीं किया। शंघाई में स्थित एक अन्य कार्यकारी ने कहा, ''यह उद्योग 10,000 पाउंड का गोरिल्ला हुआ करता था। अब हम चिम्पांजी के आकार तक सिमट रहे हैं।'' इस तरह चीन ने अपने निजी क्षेत्र का गला घोंट रखा है।

मुख्यमंत्री के हाथों नक्सल हिंसा से 70 प्रभावितों को मिला विभिन्न विभागों में नियुक्ति आदेश

मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिला अस्पताल को सौ बिस्तर से बढ़ाकर दो सौ बिस्तर करने की घोषणा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर के जिला अस्पताल को सौ बिस्तर से बढ़ाकर दो सौ बिस्तर करने की घोषणा के साथ ही अंचल के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत नक्सल पीड़ित परिवार के 70 आश्रितों को शासकीय नियुक्ति आदेश पत्र भी सौंपा और 19 हजार से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 14 करोड़ 9 लाख रूपए की बोनस राशि भी वितरित की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बीजापुर जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत नक्सल पीड़ित परिवार के आश्रितों को शासकीय नियुक्ति आदेश और तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 263 करोड़ 66 लाख से अधिक की लागत से 209 के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 228 करोड़ 53 लाख के 145 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 35 करोड़ 13 लाख के 64 विकास कार्य का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में बीजापुर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, भोपालपटनम में 132 केव्ही की विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, 33 नए स्कूल खोलने, केंद्रीय पुस्तकालय और विशेषज्ञ चिकित्सकों को राष्टीय स्वास्थ्य मिशन से जोड़ने की घोषणा की। साथ ही प्रयास आवासीय विद्यालय और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग की व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में कहा कि बस्तर क्षेत्र में विकास कार्य को गति दी जा रही है। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से माओवाद-आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, खनिज, वन संपदा से परिपूर्ण है। साथ ही यहां के निवासी भी ऊर्जावान है। प्रदेश के विकास में यहां के लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, वनमंत्री और बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, लोकसभा क्षेत्र बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंर्तगत गृह प्रवेश (चाबी वितरण) और आवास स्वीकृति पत्र, तेंदूपत्ता बोनस, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत राशि, किसान क्रेडिट कार्ड, सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त नियद नेल्ला नार हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, स्व सहायता समूह चक्रीय निधि, आय, जाति-निवास प्रमाण पत्र और युवाओं को खेल सामग्री का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभागीय स्टालों का निरीक्षण कर वन अधिकार प्रमाण पत्र, विश्वकर्मा योजना का प्रमाण पत्र, ई रिक्शा का वितरण सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों का सामग्री वितरण किया।

बस्तर अब शांति की ओर हो रहा अग्रसर :साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर प्रवास के दौरान विश्रामगृह में आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सली हिंसा से पीड़ित युवाओं से संवाद किया। ये युवा छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत पुलिस विभाग में भर्ती होकर माओवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नक्सल संगठन को छोड़कर पुनर्वास नीति से लाभान्वित होने वाले युवाओं से मिलकर खुशी जाहिर की और कहा कि बस्तर अब शांति की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विगत दिवस नक्सलियों की हिंसा के शिकार 55 से ज्यादा नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली जाकर महामहिम राष्टपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से मिले और नक्सलवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा के शिकार लोगों की बातों को सुनकर बहुत ही दुख लगा कि निर्दोष लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय से संवाद के दौरान नक्सली पीड़ित नव आरक्षक सुमित्रा ने बताया कि उनके पिता की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई थी।

छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत वे आरक्षक के पद पर नियुक्त हुए है। शासन के पुनर्वास नीति नक्सल पीड़ित परिवार के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं चेरकंटी निवासी मंगल मोड़ियम पूर्व में 19 वर्षों तक नक्सल संगठन में शामिल था। माओवादियों के खोखली विचारधारा को छोड़कर आत्मसमर्पण किया, जिन्हें पुनर्वास नीति के तहत पुलिस विभाग में नियुक्ति मिली।

प्रयास विद्यालय के प्राचार्य को हटाया गया

रायपुर. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने प्रयास विद्यालय सड्डू के प्राचार्य को हटा दिया गया है. अरविंद कुमार को प्रभार सौंपा गया है. मंजूला तिवारी, प्रभारी प्राचार्य / प्रशासकीय अधिकारी प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर को प्रयास आवासीय विद्यालय बालक सड्डू रायपुर का अतिरिक्त संपूर्ण प्रभार सौंपा गया था. उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया है. अरविंद कुमार जायसवाल, व्याख्याता / प्रभारी सहायक संचालक, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय नवा रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत तक प्राचार्य / प्रशासकीय अधिकारी, प्रयास आवासीय विद्यालय (अजजा) बालक सड्डू जिला रायपुर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर, जिला रायपुर का संपूर्ण प्रभार सौंपा गया है.-

न्याय यात्रा से हम जनता के मुद्दे उठाने में सफल रहेः बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि पिछले 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरूआत हुई और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन राजधानी रायपुर में विराम हुआ। यह यात्रा बाबा गुरू घासीदास की तपोभूमि का दर्शन कर तमाम वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरूआत की। पहले दिन 24 किमी की यात्रा तय कर कसडोल लवन में रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन लवन से शुरू कर रोहांसी तक 23 किमी की यात्रा तय किये। तीसरा दिन रोहांसी से शुरू कर भैसा तक लगभग 29.2 किमी से अधिक और चौथा दिन भैसा से शुरू कर सारागांव 24 किमी की सफर तय किया। पांचवा दिन सारागांव से सड्डू तक लगभग 18 किमी की यात्रा तय किया। इस तरह से लगभग 125 किमी से अधिक छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा क्षेत्र और जनता के बीच रहे। यात्रा निकलने से पहले प्रतिदिन सबेरे पत्रकार वार्ता फिर दोपहर भोजन के बाद पत्रकार वार्ता फिर चलते चलते वन टू वन चर्चाएं हुई, इस तरह से कुल 10 पत्रकारवार्तायें और 150 से अधिक वन टू वन या सिंगल बाईट हुई। इस पत्रकार वार्ता में तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किये। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किये। धनेन्द्र साहू ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।

हमारी यात्रा का मकसद सोई हुई सरकार को जगाने का था, जिस तरह से 9 से 10 महिने की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को सुरक्षित करने में विफल हुई। लगातार छत्तीसगढ़ में घटनायें घट रही है। अपराध बढ़ रहे है। अपराधियों का हौसला चरम पर है। ये सरकार लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। माता बहने सुरक्षित नहीं है, आश्रम छात्रावास में छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में जनता के मन में डर और भय का माहौल बना हुआ है। प्रदेश की जनता दहशत में है। सरकार पर से जनता का भरोसा उठ चुका है।

10 महीने की भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा तोड़ दिया है। 6 दिन की यात्रा में हम जनता से मिले, उनसे चर्चा भी किये।

ढाई करोड़ की लागत से बनेगा रायगढ़ एसपी कार्यालय भवन

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुख्य आतिथ्य में आज कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के नवीन भवन का भूमिपूजन कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ। लगभग 2.50 करोड़ की लागत से एसपी कार्यालय का नवीन भवन पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में तैयार होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जिले में कलेक्टर एवं एसपी कार्यालय एक ऐतिहासिक धरोहर होता है। कलेक्टर कार्यालय के नजदीक में एसपी कार्यालय के नवीन भवन बनने से जिला न्यायालय, कलेक्टर एवं एसपी कार्यालय की दूरी कम होने के साथ ही लोगों को कार्यों के लिए सहूलियत मिलेगी, जिससे कार्य की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए संबंधित ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शहर के बीचो बीच स्थित एसपी कार्यालय का कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस विभाग ही उसका उपयोग करें। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि रायगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाएं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.